● वर्ष-5
● अंक-262
रायपुर, शुक्रवार
19 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› तीन महीनों में मिलीं 11 हजार 808 दुर्लभ...

पेरिस में बोले प्रधानमंत्री मोदी

अकेले भारत में दुनिया के 50 फीसदी डिजिटल ट्रांजैक्शन

नईदिल्ली ›› एजेंसी

फ्रांस के पेरिस में आयोजित हो रहे यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी उत्सव विवाटेक 2026 के 10वें संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस साल इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन में भारत एआई कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बड़े बदलाव के दौर में तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के काम आए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए सिरे से परिभाषित करते हुए कहा कि भारत के लिए एआई का सीधा मतलब ऑल इंक्लूसिव यानी सबका समावेश और सबका कल्याण है।

भारत-ईयू व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को दोनों क्षेत्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साल की शुरुआत में संपन्न हुआ यह ऐतिहासिक समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के नए रास्ते भी खोलेगा। यह टैलेंट (प्रतिभा), टेक्नोलॉजी (तकनीक) और टूरिम (पर्यटन) के आदान-प्रदान के लिए कई नए रास्ते तैयार करेगा। इस साल भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष की शुरुआत के साथ फ्रांस एक बेहद महत्वपूर्ण पुल की भूमिका निभा रहा है, जो भारत और पूरे यूरोप के टेक इकोसिस्टम को एक-दूसरे के बेहद करीब ला रहा है।

> यह ऐतिहासिक समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के नए रास्ते भी खोलेगा। साल 2026 भारत और यूरोप के संबंधों के लिए बेहद खास है।
>
> *नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

इनोवेशन के लिए 50 अरब डॉलर की बड़ी मदद: वैश्विक निवेशकों और टेक कंपनियों को भारत में आमंत्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, जहां सरकार नियमों को आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सबसे यादा ध्यान दे रही है। इनोवेशन से लेकर प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने तक के सफर के लिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को 50 अरब डॉलर से अधिक के प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे किफायती डाटा और सबसे सस्ती ग्रीन एनर्जी भी उपलब्ध करा रहा है।

पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में तकनीक के दम पर भारत में आए महा-बदलाव का खाका भी पेश किया। उन्होंने बताया कि भारत आज तकनीक का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन, शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है। आज दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन का आधा हिस्सा अकेले भारत में होता है। भारत की यह ताकत अब फ्रांस में भी दिखाई दे रही है, जहां लोग पेरिस के मशहूर एफिल टावर और पेरिस एयरपोर्ट पर भी यूपीआई के जरिए आसानी से भुगतान कर पा रहे हैं। डिजीलॉकर जैसी डिजिटल पब्लिक गुड्स आज दुनिया के सामने मिसाल हैं।

सरकार राह बनाएगी, इंडस्ट्री करेगी कमाल

प्रधानमंत्री ने देश की नई टेक नीति को साफ करते हुए एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है। सरकार रास्ता बनाएगी और इंडस्ट्री इनोवेशन करेगी, स्टार्टअप्स नए बदलाव लाएंगे और ग्लोबल पार्टनर्स हमारे साथ मिलकर इसे बड़े पैमाने पर स्केल करेंगे। पीएम मोदी ने सम्मेलन में मौजूद सभी दिग्गजों से अपील की कि वे आगे आएं, भारत के साथ मिलकर काम करें और एक ऐसी तकनीक विकसित करें जो पूरी दुनिया के जीवन को बेहतर बना सके।

मानसून सत्र: 15 दिनों में परिसीमन पारित कराने की रणनीति

- परिसीमन 2011 जनगणना के आधार पर, 2029 से लागू होगा।
- एनडीए विपक्षी समर्थन से दो-तिहाई बहुमत जुटाने में जुटा।

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट से उत्साहित मोदी सरकार ने महिला आरक्षण एवं परिसीमन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए सरकार की ओर से जहां गैरकांग्रेसी दलों से नए सिरे से संपर्क साधा जा रहा है, खासतौर पर द्रमुक को विधेयक में हर राज्य में आनुपातिक आधार पर 50 फीसदी सीटें बढ़ाने संबंधी प्रावधान जोड़ने का आश्वासन दिया गया है। द्रमुक के साथ त्रिभाषा फॉर्मूले पर भी बीच का रास्ता निकालने पर बातचीत हो रही है।

राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत की बाधा पार कर चुकी सरकार के सामने असली चुनौती लोकसभा की है। वहां द्रमुक के बिना सरकार की बात नहीं बनने वाली। यही कारण है कि उसे मनाने के मोर्चे पर खुद गृह मंत्री अमित शाह जुटे हैं। चूंकि तमिलनाडु चुनाव के नतीजों के बाद द्रमुक ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली है। सरकार को उम्मीद है कि संबंधित बिल सहित कुछ अन्य सियासी मुद्दों पर द्रमुक के साथ बीच की राह निकाली जा सकती है।

द्रमुक पर दारोमदार

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अगर शिवसेना यूबीटी में टूट से सरकार के पास सांसदों के समर्थन का आंकड़ा 324 हो जाएगा, जो दो-तिहाई बहुमत (360) से 36 कम है। ऐसे में 22 सांसदों वाली द्रमुक की भूमिका अहम है।गर सरकार को द्रमुक का साथ मिला तो समर्थन का आंकड़ा 346 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में 14 अतिरिक्त सांसदों का आंकड़ा जुटाने के लिए पार्टी एनसीपी पवार (7), वाईएसआर (4), जेएमएम (3) जैसे कुछ गैरकांग्रेसी दलों से समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू करेगी।

सपा से भी संपर्क साधेंगे

सरकार की रणनीति प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के लिए सपा (37) से भी संपर्क साधने की है। एक मंत्री के मुताबिक, अगर द्रमुक का साथ मिला, तो संविधान संशोधन बिल की राह आसान हो जाएगी।

मानसून सत्र में फिर आएगा महिला आरक्षण बिल

सूत्रों के अनुसार बदले माहौल में विपक्षी दलों और सदस्यों के भाव बदल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हर सदस्य हर राज्य में बढ़ने वाले 50 फीसद सीट को लेकर उत्साहित है क्योंकि तभी उनकी खुद की सीट सुरक्षित रहेगी। दक्षिण के राज्यों को खासतौर पर यह उत्साहित करता है। उस वक्त द्रमुक ने केवल विधानसभा चुनाव के कारण इसका विरोध किया था। अब जबकि पार्टी चुनाव हार चुकी है और विपक्ष के आइएनडीआइए से बाहर आ चुकी है तो केवल इसका आकलन किया जा रहा है कि अब रुख बदलने से पार्टी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं महावीर के विचार : ओम बिरला

- अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मसंयम के संदेश की आज पूरे विश्व को आवश्यकता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने जैन मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो रहे पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज को नमन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि आचार्य पद केवल एक पद नहीं, बल्कि तप, त्याग, ज्ञान और समाज को दिशा देने वाली साधना का सर्वोच्च प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान समय में जब विश्व तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, तब जैन दर्शन की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं।

श्री बिरला ने कहा कि पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज का आचार्य पदारोहण संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव का क्षण है। वहीं शतावधानी हंसभद्र मुनि जी महाराज ने अपनी विलक्षण स्मरणशक्ति, ज्ञान और साधना के बल पर देशभर में विशेष पहचान बनाई है। उनके तप और साधना से समाज को नई दिशा मिल रही है।

उन्होंने कहा कि भौतिक संसाधन केवल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक सुख आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होता है। जैन संतों का तपस्वी जीवन समाज को प्रेरणा देता है और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने सभी जैन संतों, साध्वियों और श्रद्धालुओं को नमन करते हुए महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा यह आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा, साधना और संस्कृति का यह विराट आयोजन पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर बन गया है।

प्रमुख समाचार

रोजगार महाअभियान : पीएम मोदी आज देंगे बड़ी सौगात

नईदिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत प्रोत्साहन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, 15 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के ज़रिए 2,400 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे। पैसे ट्रांसफर करने से पहले, प्रधानमंत्री इस स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले कुछ युवा कर्मचारियों (जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं) और नियोक्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे। मनसुख मंडाविया ने कहा कि विज्ञान भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश भर के 200 औद्योगिक क्लस्टरों में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में किया जाएगा। इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक साथ रीजनल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य के श्रम मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

'स्टूडेंट्स इको' से जुड़कर शिक्षा रोजगार पर उठाएं आवाजः राहुल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को छात्रों और नौकरी चाहने वालों से हाल ही में शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद शिक्षा, परीक्षाओं और रोज़गार से जुड़े उनके मुद्दों को सीधे सरकार तक पहुंचाना है। एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने हिंदी में लिखा कि अगर आपने पेपर लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी या बहुत ज़्यादा फ़ीस का दर्द सहा है। अगर इस सिस्टम ने आपके सपने तोड़ दिए हैं। अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी है। तो सुनिए: 'स्टूडेंट्स इको' आपकी आवाज़ है। उन्होंने इस मुहिम को सिर्फ़ एक मुहिम से कहीं ज़्यादा बताया और इसे सरकार के सामने सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाओं और सम्मानजनक रोज़गार से जुड़ी माँगें उठाने का एक मंच कहा। गांधी ने सुझाव देकर और इससे जुड़ी याचिका पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल होने की अपील की। और ज़ोर देते हुए कहा कि आपका एक हस्ताक्षर इस लड़ाई को मज़बूत करेगा।

रिताब्रत बनर्जी ही बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष : हाईकोर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच सत्ता संग्राम अब अदालती गलियारों में पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को एक बड़ा कानूनी झटका देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें बागी टीएमसी विधायक रिताब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। हाई कोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल रिताब्रत बनर्जी अपने पद पर बने रहेंगे और स्पीकर रथिन बसु का फैसला पूरी तरह प्रभावी रहेगा। फिलहाल, रिताब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और स्पीकर रथिन बसु का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पीकर के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। उन्होंने सभी पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

दलितों पर अत्याचार के लिए यादव-मुस्लिम जिम्मेदारः राजभर

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी के समर्थक ही पूरे राज्य में दलितों पर होने वाले अत्याचारों के मुख्य दोषी हैं। राजभर ने एक्स पर सपा के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे का मज़ाक उड़ाते हुए इसका नया मतलब निकाला और कहा कि यह कुछ खास समुदायों द्वारा दलितों के खिलाफ हिंसा का प्रतीक है। राजभर ने कहा कि क्या आपको लगा कि ओम प्रकाश राजभर भूल गए? पीडीए यानी पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक की दूसरी किस्त जारी नहीं करेगा? दलितों पर सपाई यादवों और सपाई मुसलमानों के अत्याचार को जोनवार और कमिश्नरेटवार सार्वजनिक नहीं करेगा? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। उन्होंने आगे लिखा कि लो लोडरों, पढ़ना-लिखना जानते हो तो आंख गड़ा के पढ़ लो यूपी पुलिस की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के हर पुलिस जोन और पुलिस कमिश्नरेट में दलितों-शोषितों पर हुए अत्याचार के मामलों में सबसे ज्यादा तुम सब ही शामिल हो।

ओपी राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता : शिवपाल यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस आरोप को खारिज कर दिया कि सपा में अंदरूनी फूट है; उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की रची हुई साजिश बताया। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने राजनीतिक फ़ायदे के लिए झूठ फैलाने के आरोप में भाजपा और उसके सहयोगियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। वे समय-समय पर साज़िशें भी रचते रहते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव में सीटें बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। उन्होंने राजभर का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि उनके बयान पैसे के लिए दिए जाते हैं। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें ट्वीट करने के लिए पैसे मिलते हैं, इसीलिए वे ऐसी बातें कहते हैं और झूठ बोलते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लेता है। एसबीएसपी नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो पहले समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे।

स्वामी विवेकानंद के योग संदेश की वैश्विक यात्रा

भारत से शिकागो और फिर हुगली तक

प्रतापराव जाधव

समूचे इतिहास में, कुछ विचार सरहदों के पार जाकर समाजों को बदलते रहे हैं। योग भारत की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है, जिसकी यात्रा प्राचीन शास्त्रों से शुरू होकर वैश्विक मान्यता तक जा पहुँची है। योग शब्द - जो संस्कृत के मूल शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है या एकत्व स्थापित करना अपने भीतर दार्शनिक चिंतन और व्यावहारिक अनुशासन की एक समग्र प्रणाली समाहित किए हुए है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति (जीवात्मा) का सार्वभौमिक चेतना (परमात्मा) के साथ मिलन कराना है। योग के प्रारंभिक बीज ऋग्वेद (लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व) में मिलते हैं, जहाँ तप और ध्यान जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलकर इन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ, जिन्होंने योग के अनेक दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। हालाँकि योग को उसका सर्वाधिक व्यवस्थित स्वरूप महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योगसूत्र (लगभग 200 ईसा पूर्व-400 ईस्वी) ने प्रदान किया- इसमें अष्टांग योग अथवा आठ अंगों वाले मार्ग का वर्णन किया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। पतंजलि के अलावा, भगवद गीता योग को जीवन जीने के गतिशील दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र की पृष्ठभूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव कर्तव्य, उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति के विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवद्गीता में वर्णित विभिन्न मार्गों में कर्म योग (नि:स्वार्थ कर्म का मार्ग), ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग) और भक्ति योग (भक्ति का मार्ग) मुक्ति प्राप्ति के तीन प्रमुख पथ माने गए हैं। अत: भारत केवल योग की जन्मभूमि ही नहीं है—यह एक जीवंत सभ्यता है, जहाँ योग सहस्राब्दियों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, और जो इसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक संरचना का अभिन्न अंग रहा है। हालाँकि, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज के शिक्षित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी बौद्धिक विचारधाराओं से प्रभावित होने और योग सहित भारत की अनेक पारंपरिक ज्ञान-परंपराओं को बदलती आधुनिक दुनिया में अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक माना जाने लगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में, स्वामी विवेकानंद

एक सशक्त स्वर बनकर उभरे, जिन्होंने लोगों को योग के वास्तविक महत्व को फिर से जानने में मदद की। स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों और विश्व धर्म संसद में दिए ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से दुनिया का ध्यान भारत की आध्यात्मिक विरासत की ओर आकृष्ट किया और योग की शाश्वत ज्ञान-परंपरा के प्रति लोगों में नया विश्वास जगाया। उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के साथ वेदांत और योग के सिद्धांत साझा किए तथा यह स्पष्ट किया कि योग केवल एक धार्मिक साधना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, आंतरिक शांति और आत्म-विकास का मार्ग भी है। विदेशों में स्वामी विवेकानंद को मिले व्यापक सम्मान और प्रशंसा ने भारतीयों के मन में अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के प्रति नया विश्वास और गौरव उत्पन्न किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो - और उसके बाद अमेरिका भर में तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अपने व्याख्यानों के माध्यम से पश्चिमी जगत को राजयोग (मन के नियंत्रण का योग), ज्ञानयोग (विवेक और ज्ञान का मार्ग), कर्मयोग (नि:स्वार्थ सेवा का मार्ग) तथा भक्तियोग (ईश्वर-प्रेम और समर्पण का मार्ग) से परिचित कराया। पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित उनकी पुस्तक राजयोग (1896), पश्चिमी समाज के लिए योग-दर्शन का परिचय कराने वाली प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभावशाली कृतियों में से एक बन गई।

राजयोग पर दिए अपने व्याख्यानों में स्वामी विवेकानंद ने योग को मानव चेतना के आंतरिक आयामों की खोज करने वाली एक व्यवस्थित और अनुभव-आधारित साधना के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानवता के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान उसकी आध्यात्मिक ज्ञान-परंपरा है, और योग उस परंपरा की सबसे गहन तथा स्थायी अभिव्यक्तियों में से एक है। उनके विचारों ने उस समय के जाने-माने बुद्धिजीवियोंऔर विचारकों का ध्यान खींचा, जिससे भारतीय दर्शन के साथ पश्चिमी देशों का जुड़ाव और बढ़ा। जो बात शायद कम चर्चित है- किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण है,- वह यह है कि पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद के कार्यों ने भारत के भीतर ही योग के पुनर्जागरण को प्रेरित किया। जब स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटे, तो वे खाली हाथ नहीं लौटे थे। वह अपने साथ एक नया आत्मविश्वास- भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गर्व की एक नई भावना लाए थे - जो पश्चिम में उनके स्वागत से और बढ़ गई थी। 1897 में भारत लौटने के बाद, स्वामी विवेकानंद ने देशभर में व्याख्यान दिए और लोगों को भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को पुन: खोजने के लिए प्रेरित किया।

यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी वापस हों स्मार्ट मीटरः अरुण वोरा

बालोद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बिजली की बढ़ती कीमतों और स्मार्ट मीटरों की कथित गड़बड़ियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बालोद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जनता पर सीधा आर्थिक अत्याचार बताया। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी जनहित में स्मार्ट मीटर वापस लेने का फैसला करना चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक संगीता सिन्हा सहित जिलाध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी मौजूद रहे।

पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही जनता पर महंगाई का बोझ लाद दिया गया है। सरकार बनने के बाद यह लगातार पांचवीं बार है जब बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे और गैर-घरेलू (कमर्शियल) दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

वोरा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 पैसे की बढ़ोतरी की थी, और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल रही थी। भाजपा सरकार ने न केवल इस राहत योजना को बंद कर दिया, बल्कि जून के महीने में ही प्रदेश के 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सामान्य से तीन गुना अधिक बिल थमा दिया। आज जनता बिजली कटौती से भी जूझ रही है और अनाप-शनाप बिलों से भी परेशान है। पूर्व विधायक ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को लूटने का जरिया बन चुका है। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर सामान्य मीटरों की तुलना में बेहद तेज भाग रहे हैं, जिससे वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा रीडिंग आ रही है। इसी बढ़ी हुई रीडिंग का बहाना बनाकर विभाग बिना उपभोक्ता की सहमति के उनका अनुबंध भार (सेंक्शंड लोड) खुद-ब-खुद बढ़ा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके बाद एग्रीमेंट से अधिक खपत बताकर उपभोक्ताओं पर भारी-भरकम अर्थदंड (पेनल्टी) जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को एक ही महीने में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से अलग-अलग बिल भेजकर भ्रमित और परेशान किया जा रहा है। अरुण वोरा ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता के विरोध को देखते हुए स्मार्ट मीटर वापस लेने का निर्णय लिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस नहीं लिया और स्मार्ट मीटरों के नाम पर चल रही इस मनमानी को बंद नहीं किया, तो कांग्रेस जनता के हक के लिए सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।लेकिन कार्रवाई के दौरान अधिकारी मीडिया से बातचीत करने से बचते नजर आए। गुरुवार सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले नगर निगम की टीम ने संबंधित स्थलों पर नोटिस चस्पा किए। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया।

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश और उसके बाद अपील खारिज होने के बाद संभव हो सकी। वहीं प्रभावित पक्ष और पूर्व पार्षद ज्ञानदास बंजारे ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सूचना के सुबह 4 बजे कार्रवाई की गई। साल 1956 से यहां रह रहे हैं और राजनीतिक कारणों से उनके वार्ड को निशाना बनाया गया है। अपर कलेक्टर ने 25 तारीख तक कार्रवाई नहीं होने की बात कही थी और अब दोबारा न्यायालय की शरण लेंगे-ज्ञानदास बंजारे,पूर्व पार्षद बोरसी भाठा वहीं एक अन्य प्रभावित व्यक्ति जीवन यादव ने बताया कि उनका मामला पहले से न्यायालय में चल रहा था और उन्हें किसी नए आदेश की जानकारी नहीं दी गई थी।हमने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में भी पूछा तो जवाब मिला कि कॉपी नही आई है,लेकिन हटाने का आदेश हो चुका है।

पीड़ित पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। जानकारी के मुताबिक पहले एसडीएम न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने अपील दायर की थी, लेकिन करीब एक सप्ताह पहले अपील खारिज कर दी गई।

धमतरी में एसपी ने किया आरक्षक को निलम्बित

धमतरी। बीते दिनों मरौद टोल प्लाजा पर ट्रक चालक से मारपीट का आरोप पुलिस कांस्टेबल पर लगा था। ट्रक चालक से कथित मारपीट के आरोपी आरक्षक पवन वर्मा को आज निलंबित कर दिया गया। आरोपी आरक्षक पवन वर्मा थाना कुरूद में पदस्थ था, जिसे आज एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर निलंबित कर रूद्री पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया। आरक्षक पवन वर्मा को पुलिस लाइन रूद्री में अटैच करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है।

दरअसल, मरौद टोल प्लाजा के पास एक ट्रक चालक के साथ आरक्षक पवन बर्मन द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने की सूचना पुलिस विभाग तक पहुंची थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी कुरूद ने पुलिस अधीक्षक धमतरी को घटना की जानकारी से अवगत कराया।

प्रारंभिक स्तर पर की गई जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरक्षक अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाया गया। जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने, तत्काल कार्रवाई करते हुए आरक्षक पवन बर्मन को निलंबित कर पुलिस लाइन रूद्री अटैच करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत प्राथमिक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि घटना के सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।

ग्राम पंडरी में घर-घर पहुंचा नल का जल

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जल जीवन मिशन के सात वर्ष पूरे होने के साथ ही देशभर में इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के विकासखंड मरवाही स्थित ग्राम पंडरी इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ जल जीवन मिशन ने केवल घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का कार्य नहीं किया, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान का नया अध्याय जोड़ा है। एक समय था जब ग्राम पंडरी की महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन पानी की व्यवस्था के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। सुबह का बड़ा हिस्सा पानी लाने में व्यतीत हो जाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के अन्य कार्य प्रभावित होते थे। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन उपलब्ध होने से ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सीधे उनके घरों में मिल रहा है। ग्राम की शीला केवट सहित अनेक महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें पानी के लिए घंटों इंतजार या दूर-दराज के जलस्त्रोतों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बचा हुआ समय अब परिवार, बच्चों की शिक्षा और आजीविका संबंधी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन का प्रभाव केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। स्वच्छ पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों में कमी आई है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को विशेष लाभ मिला है। साथ ही, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। ग्राम पंडरी आज इस बात का प्रमाण है कि जब योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी साथ-साथ चलती है, तो ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। गाँव के घरों में बहता स्वच्छ जल केवल सुविधा का प्रतीक नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास की नई पहचान बन चुका है। जल जीवन मिशन ने ग्राम पंडरी में विकास की ऐसी धारा प्रवाहित की है, जिसने ग्रामीणों के जीवन को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया है। घर के आंगन में बहती स्वच्छ जलधारा और ग्रामीणों के चेहरों पर दिखती संतुष्टि की मुस्कान इस मिशन की सफलता की सबसे बड़ी कहानी कहती है। यही जल जीवन मिशन के सात वर्षों की वास्तविक उपलब्धि है, जिसने गाँवों में खुशहाली और विकास का नया अध्याय लिखा है।

हसदेव नदी के किनारे लोगों ने बना लिए मकान

कोरबा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा हसदेव बांगो बांध% कोरबा के मचाडोली में स्थापित है। ये बांध इस साल समय से पहले ही भरने लगा है। वर्तमान में बांध में 56 फीसदी पानी जमा हो चुका है, जो हर साल इस सीजन में होने वाले जलस्तर से काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है, तो बांध के गेट कभी भी खोलने पड़ सकते हैं। गेट खुलने की स्थिति में हसदेव नदी के किनारे बसे निचले गांवों और बस्तियों में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन नदी के ठीक किनारे बने अवैध और अस्थायी मकानों ने चिंता और बढ़ा दी है। लोगों ने अस्थाई मकान और कई तरह का ढांचा यहां तैयार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि पानी भरा तो सबसे अधिक समस्या प्रशासन के समक्ष खड़ी होती है। बचाव कार्य और मुआवजा की मांग होती है। लेकिन समय रहते कोई प्रयास नहीं किए जाते।

शहर से लगे सीतामणी क्षेत्र में लोगों ने बेजा कब्जा कर मकान का निर्माण किया है। ईंट सीमेंट और एस्बेस्टस सीट के छोटे मकान से लेकर ठेलानुमा ढांचा यहां मौजूद हैं। मकान ऐसे ही स्थान पर बनाए गए हैं, जो हसदेव नदी के एकदम किनारे मौजूद हैं। बांध से पानी छोड़े जाने पर इन इलाकों में पानी भर जाता है। लगभग हर साल यहां पानी भरता है। बावजूद इसके लोग यहां मकान का निर्माण करने से नहीं चूकते। इस वर्ष भी यही स्थिति बनी हुई है। समय रहते इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता। पानी भरने के बाद जब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तब प्रशासन के समक्ष बचाव कार्य और मुआवजा प्रकरण तैयार करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता। हसदेव बैराज दर्री से पानी छोड़ने की स्थिति में कोरबा के चारपारा, खैरभवना, बरमपर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, सीतामणी, ईमलीडूग्गू, कुदुरमाल, बरीडीह, कटबितला, मोहरा, झींका, ठिठोली, चिचौली को बाढ़ संभावित गांव बताया गया है। जबकि जांजगीर-चांपा जिले के चांपा और देवरी भी संभावित गांवों में शामिल हैं।

मिनीमाता बांगो बांध की क्षमता 358 ।10 मीटर है। वर्तमान में यह 56त्न है। जल स्तर जब 358 मीटर के नीचे जाता है, यानी बांध में कुल जलभराव 85 से 90 फीसदी के बीच रहता है। तब गेट बंद किया जाता है। बांध में जलस्तर को कुल जल धारण क्षमता के 85 से 90 फीसदी के मध्य मेनटेन करके रखा जाता है।

जल क्षमता इससे अधिक होने पर गेट खोलकर पानी नदी में प्रवाहित किया जाता है। खरीफ सीजन में बांगो बांध के जरिए 2 लाख 47 हजार हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। फिलहाल बांध में इतना पानी है कि इस सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जा सके।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा में रोजगार मेला 300 युवाओं के आए आवेदन

कोरबा। जिला रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में कुल 6 कंपनियों के 641 रिक्त पदों के लिए आवेदन युवाओं से मंगाए गए। रोजगार कार्यालय के ई रोजगार पोर्टल पर इन सभी पदों के लिए मात्र 300 युवाओं ने आवेदन किया। बेरोजगारी की दर इतनी अधिक होने के बाद भी रोजगार कार्यालय के रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या काफी कम रही। रोजगार कार्यालय में पंजीयन के आधार पर युवाओं को आमंत्रित किया जाता है। इसी के आधार पर रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास होता है। इन कंपनियों ने रोजगार मेले में लगाया कैंप सतरेंगा महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एलआईसी कोरबा आईसेक्ट कोरबारॉयल हंटर कोरबा परीक्षण ह्यूमन रिसोर्स डिपार्मेंट 641 पदों पर आवेदन मंगाए गए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका देने के लिए कंपनियों ने रोजगार मेला कैंप लगाया और इंटरव्यू का आयोजन किया। इन सभी कंपनियों में कुल मिलाकर 641 पदों पर आवेदन युवाओं के मंगवाए गए थे।

कोर्ट ने कहा- आरक्षण का लाभ सिर्फ मूल राज्य में मान्य

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिल सकता है, अभ्यर्थी जहां का मूल निवास है। कोर्ट ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (क्क्ङ्कञ्जत) के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया के मामले में एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कलेक्टर कोरिया के आदेश को सही ठहराया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई। दरअसल, कोरिया जिले में 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTG) के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हुई थी। आवेदिका रामवती ने भृत्य पद के लिए आवेदन किया था। चयन के बाद उसे 8 अगस्त 2022 को नियुक्ति भी दे दी गई। हालांकि बाद में दस्तावेजों की जांच हुई, तो पता चला कि महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली है और उसका जाति प्रमाण पत्र भी वहीं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इसे आधार बनाकर कलेक्टर कोरिया ने 27 अक्टूबर 2022 को उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी।

चरित्र शंका पर हदे पार पति ने पत्नी कालिख भी पोती

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए हैवानियत की सारी हदें पार दी। पति ने पहले पत्नी का बाल काटकर मुंडर किया। फिर मारपीट कर बच्चे और खुद का पेशाब पिलाया और उनके उपर कालिख भी पोती। पूरा मामला पंडोपारा स्थित काटकोना गांव का है। बताया जा रहा कि दोनों का 2006 में लव मैरिज हुआ था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में उनके चारों बच्चे भी मौजूद दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला सूरजपुर जिले के करंजी की रहने वाली है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और पति पर अमानवीय प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पटना पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पति मंत्रालय में सरकारी गाड़ी चलता है। 2006 में दोनों का लव मैरिज हुआ था। उनके दो बेटे और दो बेटी है। उनकी पत्नी एक साल से अलग रह रही थी।

ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा गांजा पकड़ाया

सक्ती। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सक्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे करीब 209 किलोग्राम गांजा को जब्त करते हुए एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल रणनीति बनाते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन कर ग्राम बोडासागर स्थित सागर फैमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध टाटा सिगना ट्रेलर क्रमांक आर जे 09 जीसी 5216 को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रेलर में रखी 8 प्लास्टिक बोरियों से कुल 40 पैकेट गांजा बरामद किया गया। प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 5 किलोग्राम था। जब्त गांजा का कुल वजन 208.965 किलोग्राम पाया गया।

महासमुंद के शासकीय स्कूलों की हालत जर्जर

महासमुंद। शाला प्रवेश उत्सव के साथ नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और बच्चे नई उम्मीदों के साथ स्कूलों की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, लेकिन महासमुंद जिले के शासकीय स्कूलों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। बच्चों के सिर पर कब छत गिर जाए, कब उन्हें करंट लग जाए, कब खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं स्कूलों में पीने के पानी का अभाव है, तो कहीं शौचालय तक नहीं हैं और कहीं अतिरिक्त कक्ष में कई कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार, महासमुंद जिले में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए कुल 1956 शासकीय स्कूल संचालित हैं, जिनमें प्राथमिक स्कूल 1276, मिडिल स्कूल 492, हाई स्कूल 65 एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 126 हैं। इन स्कूलों में वर्ष 2025-26 में 1 लाख 41 हजार 503 छात्र अध्ययनरत थे। जिले के 54 स्कूल पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुके हैं और इस्तेमाल के लायक नहीं हैं।

बाबा बालक दास के आश्रम पर चला बुलडोजर

बालोद। बालोद रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण के आरोपों से घिरे बाबा बालक दास के आश्रम जामडीपाठ में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पूरा आश्रम छावनी में तब्दील हो चुका है और भारी पुलिस बल तैनात है। सुबह से कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित वन मंडल अधिकारी आश्रम के अंदर हैं।

वहीं आदिवासी समाज ने अपने देव स्थल में पूजा पाठ भी की है। कलेक्टर दिव्या मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, वन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल सहित जिले के आला अधिकारी आश्रम परिसर में कार्रवाई के दौरान मौजूद थे।

आपको बता दें कि पाटेश्वर धाम में जलकैना के पास बने बाउंड्री वाल पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी समाज ने आश्रम के अंदर आकर अपने देवस्थल पर पूजा भी की है। समाज ने आगामी 20 जून को इस पूरे मामले को लेकर संरक्षण जातरा के आयोजन करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को 20 जून के आव्हान से जोड़कर देखा जा रहा है।आश्रम से 5 किलोमीटर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है।

पूरे मामले को लेकर विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो समाज के साथ हैं, यदि कोई आदिवासी पट्टा मांगे, कोई किसान एक डिसमिल जमीन मांगे तो नहीं दिया जाता। लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में धाम बनाया जा रहा है।

प्रशासन ने पूरे मसले को लेकर आदिवासी समाज और बाबा के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। संत बाबा बालक दास ने अब तक इस मामले को लेकर केवल ऑफ रिकॉर्ड इतना ही कहा है कि बातचीत के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। संत का पक्ष हमेशा निष्पक्ष होता है। वहीं आदिवासी समाज इस पूरे मामले को लेकर शांत होता नहीं दिख रहा है। समाज ने 20 जून को देव स्थल पर संरक्षण जातरा का जो आह्वान किया गया है, उसे लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन आदिवासियों को शांत करने के लिए आश्रम के खिलाफ एक्शन ले रहा है।

दुनिया के हर देश से रिश्ते बना रहे पीएम मोदी- विजय बघेल

दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने बाद हुई पहली द्विपक्षीय बैठक को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और उनकी विदेश नीति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत और मित्रतापूर्ण रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के हर देश के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे हैं।उनका मानना है कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में प्रधानमंत्री की विदेश नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोनों नेता एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों देशों के बीच यह संवाद भारत-अमेरिका संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी भी देश के विकास, व्यापार, निवेश और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारत आज जिस प्रकार विश्व के प्रमुख देशों के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बना रहा है, उससे देश को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा - विजय बघेल, सांसद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विचारधारा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत की बात दुनिया गंभीरता से सुन रही है और वैश्विक मुद्दों पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गुरुवार को यहां लोकभवन में वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोक भवन में उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना एवं लोक भवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी।

राज्यपाल डेका ने किया लोकसभा अध्यक्ष श्री बिड़ला का आत्मीय स्वागत

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला के लोकभवन आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह,केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी श्री बिड़ला का स्वागत किया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसः उद्योग मंत्री कांकेर के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल

रायपुर। प्रदेश के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए राज्य शासन द्वारा मंत्रिमंडल, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है। इसी तारतम्य में वाणिज्य उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन रविवार 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला उत्तर बस्तर के मुख्यालय कांकेर में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री साय की पहल से कुनकुरी की बिजली व्यवस्था हुई और मजबूत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से कुनकुरी की बिजली व्यवस्था हुई और मजबूतमुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के तहत जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण सौगात मिली है। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र कुनकुरी में 3.15 एमवीए क्षमता के पुराने पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। साथ ही नगर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 11 केवी फीडर का निर्माण एवं विद्युत प्रवाह प्रारंभ करने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। नए ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए विभाग द्वारा व्यापक तकनीकी तैयारियां की गईं। कार्यस्थल पर आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने हेतु दो डीपी को स्थानांतरित किया गया, अनुपयोगी नियंत्रण कक्ष को हटाया गया तथा पुराने ट्रांसफार्मर प्लिंथ का मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया। सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि से क्षेत्र की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं नए 11 केवी फीडर के शुरू होने से विद्युत भार का बेहतर वितरण संभव होगा, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुचारू एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बलरामपुर में होगा भव्य सामूहिक योगाभ्यास

रायपुर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में व्यापक स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के खेल मैदान में प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर योगाभ्यास करेंगी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी सहारा, शिकायत पर घर पहुंचा राशन कार्ड

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेश में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले की निवासी श्रीमती सुनीता देवी को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से राशन कार्ड प्राप्त होने पर बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पिपरपान निवासी श्रीमती सुनीता देवी लंबे समय से राशन कार्ड बनवाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। राशन कार्ड नहीं बनने के कारण उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ भी नहीं मिल रहा था। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जांच और प्रक्रिया पूरी की।

छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

■ राज्य में 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने की।

बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रणवीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित शराब व्यसन मुक्ति अभियान की प्रगति, नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन तथा भविष्य की कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक 6 अक्टूबर 2023 के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन एवं विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

समिति ने नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया । केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में ऐसे केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। 5 नये नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे।

बैठक में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समिति का मानना है कि इससे केन्द्रों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों तथा व्यय की समीक्षा भी की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में एनसीओआरडी एवं एनएमबीए के प्रभावी क्रियान्वयन में योजनांतर्गत गठित समूहों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। समिति ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय की सहभागिता आवश्यक है।

बैठक के दौरान नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से विभागीय समन्वय को और मजबूत करने, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समुदाय आधारित जनजागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि महाविद्यालय रायपुर में तीन दिवसीय योग कार्यशाला का शुभारंभ

रायपुर। भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2026) के उपलक्ष्य में कृषि महाविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा तीन दिवसीय योग कार्यशाला एवं योग प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला 18 से 20 जून 2026 तक आयोजित की जा रही है।

कार्यक्रम के प्रथम दिवस कृषि महाविद्यालय, रायपुर के कृषि मंडपम में आयोजित योग कार्यशाला में लगभग 85 प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

योग प्रशिक्षक सुश्री संगीता निर्मलकर ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने योग के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन एवं तनाव प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बताया। यह योग कार्यशाला 20 जून 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 7:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके उपरांत 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

20 जून से कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

मिशन 2028 की बड़ी तैयारी, राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अभनपुर में 20 जून से 29 जून तक कांग्रेस की दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को प्रशिक्षण देकर धार देने जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी 21 जून को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शिविर में ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। जिला अध्यक्षों को मैदान पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। साथ ही संगठन, फील्ड विजिट और सामाजिक-राजनैतिक एक्टिविटी पर ट्रेनिंग देंगे।

एआईसीसी से जारी शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी 21 जून को दोपहर दो बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2:45 बजे बाय रोड सीधे अभनपुर स्थित प्रशिक्षण स्थल के लिए रवाना होंगे। शाम 5:30 बजे तक जिला अध्यक्षों को संगठन, फील्ड विजिट और सामाजिक-राजनैतिक एक्टिविटी पर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद 6:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी राहुल गांधी 4 घंटे 40 मिनट छत्तीसगढ़ में रहेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित है। शिविर अभनपुर के अग्रवाल रिसोर्ट में 20 से 29 जून तक पूरी तरह आवासीय होगा। एआईसीसी का प्रशिक्षण विभाग इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। दीपक बैज ने कहा, जिला अध्यक्षों को फील्ड विजिट, सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों और जमीनी राजनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत कर सकें।

शिविर में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी एक साथ एकजुट होकर मंच पर नजर आएंगे। एआईसीसी के सभी राष्ट्रीय महासचिव भी शिविर में शामिल होंगे। दीपक बैज के मुताबिक यह शिविर जिला अध्यक्षों को जमीनी फीडबैक लेने, जनता से संवाद और संगठन खड़ा करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगा।

कांग्रेस का संगठन सृजन के बाद यह पहला बड़ा प्रशिक्षण है। कांग्रेस 2023 की हार के बाद बूथ स्तर की कमजोरी को सबसे बड़ी वजह मानती है। इसी को दूर करने के लिए जिला अध्यक्षों को फील्ड विजिट + सोशल एक्टिविटी का फॉर्मूला सिखाया जाएगा। राहुल गांधी की एक दिन की ट्रेनिंग को मिशन 2028 की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के रायपुर प्रवास पर मंत्री केदार कश्यप का विवादित बयान

रायपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के 21 जून को रायपुर में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी के लंबे समय बाद हो रहे छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेसियों से राहुल गांधी का स्वागत दारू से पैर धोकर करने की बात कही है।

मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस अपने आका को खुश करने के लिए बहुत सारे नवाचार करती है। पिछली बार जब प्रियंका गांधी आई थी, तो उनके लिए कांग्रेसियों ने गुलाब के पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी। कांग्रेस अपने पांच साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार में डुबी रही, शराब घोटाला किया। अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं, तब कांग्रेस उनका चरण दारू से धोकर स्वागत करे, ऐसी हमारी शुभकामना है।

रेत उत्खनन विवाद में कोरिया जिले में भाजपा नेता लल्ला सिंह की हत्या पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जहां-जहां ठेका मिला था, वहां लंबी-लंबी सुरंगें बनी थी। रेत खदान के नजदीक सड़कों पर रेत का डंप लगा हुआ था। आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। वहीं अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कुछ घटनाएं होती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, ताकि ऐसे लोगों को संरक्षण न दिया जाए।

वहीं महंगी बिजली पर कांग्रेस के आंदोलन पर केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। लोगों को प्रताड़ित करना कांग्रेस का काम है। अन्य प्रदेशों की तुलना में बिजली का टैरिफ बहुत कम है। इसके अलावा सूर्यघर योजना से मुफ्त बिजली को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में बिजली क्राइसिस खत्म होगा।

कोरिया में भाजपा नेता की हत्या पर गरमाई सियासत

एक-दूसरे के खून के प्यासे बने भाजपाई: बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत उत्खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता की हत्या के मामले में अब सियासत पूरी तरह गरमा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रेत की कालाबाजारी के चक्कर में भाजपाई एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं और अपने ही पार्टी के नेताओं की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

बता दें कि मंगलवार को कोरिया जिले में रेत उत्खनन को लेकर भाजपा नेताओं के बीच विवाद हुआ था, जो रात में खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान फॉर्च्यूनर वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसमें भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार की मौके पर जलकर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे उनके रिश्तेदार वीरू सिंह की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना में तीन अन्य घायलों का अंबिकापुर अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अक्षय त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी शामिल हैं। बाकी तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

दीपक बैज ने घटना के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच गैंगवार का कारण बन चुका है। पूरे प्रदेश में रेत के लिए खून-खराबा मचा हुआ है। कोरिया जिले में बेहद ही डरावनी घटना घटी, एक भाजपा नेता ने दूसरे भाजपा नेता, उसके भाई और साथी को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। सरकार के संरक्षण में रेत माफिया बेलगाम हो चुका है। भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री सीधे रेत के कारोबार में लिप्त है और उनके संरक्षण में अपराधी आतंक मचा रहे हैं।

दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, कहीं चाकूबाजी हो रही है। पूरे प्रदेश के रेत घाटों में खुलेआम माफिया राज चल रहा है और सरकार सोई हुई है।

गृह निर्माण मंडल की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

निजी बिल्डर के अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेजबहार फेस-1 कॉलोनी स्थित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मंडल की टीम ने एक निजी बिल्डर द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित सड़क को हटाकर भूमि को अपने कब्जे में लिया। अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि भविष्य की आवासीय परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखी गई है।

जानकारी के अनुसार, दीनदयाल आवास योजना के तहत कलेक्टर रायपुर के 3 फरवरी 2006 के आदेश के माध्यम से ग्राम सेजबहार और ग्राम दतरेंगा की कुल 21.538 हेक्टेयर (करीब 53.19 एकड़) भूमि गृह निर्माण मंडल को आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए आबंटित की गई थी। इसमें ग्राम सेजबहार के खसरा नंबर 162/1 के हिस्से तथा ग्राम दतरेंगा के खसरा नंबर 341/1 और 341/3 की भूमि शामिल है। इस परियोजना के लिए 17 मई 2006 को विकास अनुज्ञा भी स्वीकृत की गई थी।

स्वीकृत ले-आउट के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुल 1435 एलआईजी (लो इनकम ग्रुप) आवासों का निर्माण किया जाना था। मंडल द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण और अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इनमें से 1327 आवास निर्धारित ले-आउट के अनुरूप बनाए गए थे, जबकि 39 भवन स्वीकृत अभिन्यास से अलग निर्मित किए गए। इस प्रकार कुल 1366 आवासों का निर्माण हुआ।

मंडल के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण भवन क्रमांक 1287 से 1345 तथा 1412 से 1431 तक कुल 79 आवासों का निर्माण नहीं हो सका। सातवें चरण के तहत 7 अगस्त 2006 को किए गए अनुबंध क्रमांक-41 में 192 आवासों के निर्माण का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत 193 एलआईजी भवन बनाए गए। हालांकि विवादित क्षेत्र में प्रस्तावित 79 आवास न तो निर्मित हो सके और न ही उनका विक्रय किया गया।

हाल ही में गृह निर्माण मंडल ने अपनी लगभग 18 हेक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया। इस प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि एक निजी बिल्डर ने मंडल की भूमि के एक हिस्से पर बिना अनुमति कब्जा कर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। सीमांकन रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद मंडल ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। कार्यपालन अभियंता नितेश कश्यप के नेतृत्व में मंडल की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से बनाई गई सड़क को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

पीडब्ल्यूडी सचिव ने मेडिकल कॉलेज के कार्यों का किया निरीक्षण

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यस्थलों पर जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को प्रगतिरत सभी कार्यों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में वर्षा ऋतु को देखते हुए सड़कों के रखरखाव एवं गड्ढा मरम्मत के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए बारिश शुरू होने के पहले सभी आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने समय पर पुल-पुलियों की भी मरम्मत करने के निर्देश दिए, ताकि बरसात में आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों और पुलों का नियमित निरीक्षण कर उनकी स्थिति पर सतत निगरानी रखने को कहा।

विभागीय सचिव ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में मैदानी अधिकारियों ने कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित व प्रगतिरत कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

श्री बंसल ने अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अंडरपास, पुल एवं अन्य संरचनात्मक निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को परेशानी से बचाने सड़कों व पुलों के काम को हर हाल में समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा, ताकि लोगों को शीघ्र बेहतर यातायात की सुविधा मिले।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होना चाहिए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. वि/यां संभाग रायपुर छ. ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-3032/NIT-6/2026-2027/ व ले लि दिनांक:16/06/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का का नाम No of Call	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
6 T0022	Electrification work of Gplus2 proposed extension in physiotherapybuilding Gplus4 multi story for PG course at Govt Physiotherapy College, Raipur, CG/ DEPOSIT **प्रथम आमंत्रण**	5.60
6 T0023	Repairing work of spilt type air conditioner to Sickle Cell Institute at Pt JNM Medical College Campus, Raipur, Chhattisgarh/DEPOSIT WORK **प्रथम आमंत्रण**	0.86

नोट:- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी दिनांक 25/06/2026 अपरान्ह 5:30 बजे तक निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट **www.cg.nic.in/pwdraipur** में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें- 1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि. वि/यां संभाग रायपुर (छ.ग.)

जी-262701525/3

दल-बदल कानून 2.0: बदलते जनादेश की नई चुनौतियां

गुंजा कपूर

भारतीय राजनीति में इन दिनों एक विचित्र दृश्य देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय दल टूट रहे हैं, नेता दल बदल रहे हैं और राजनीतिक निष्ठाएं पहले से कहीं अधिक तरल दिखाई देती हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में जनादेश का मालिक कौन है? दल-बदल भारतीय राजनीति में कोई नई घटना नहीं है। 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल ने इतनी बार दल बदला कि आया राम गया राम भारतीय राजनीति का स्थायी मुहावरा बन गया। आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र में सरकारें गिरती और बनती रहीं। अंतत: 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून लाना पड़ा, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनियंत्रित राजनीतिक आवाजाही लोकतंत्र की स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। 1999 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई। उसी वर्ष शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इन नेताओं ने केवल दल नहीं बदला; उन्होंने नया राजनीतिक मंच बनाया और अंतत: जनता से नया जनादेश प्राप्त किया। मतदाता को यह अधिकार दिया गया कि वह उनके नए राजनीतिक मार्ग पर मोहर लगाए या उसे खारिज कर दे। अधिकांश मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधि से अधिक दल, चुनाव चिन्ह और शीर्ष नेतृत्व के आधार पर मतदान करते हैं। कई चुनावों में मतदाता स्थानीय उम्मीदवार को नहीं, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक कथा को वोट देता है जिसका वह उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, आज व्यापक रूप से यह माना जाता है कि बड़ी संख्या में मतदाता स्थानीय उम्मीदवार से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनकी छवि और उनके नाम पर मतदान करते हैं। यही प्रवृत्ति विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के करिश्माई नेताओं के साथ भी दिखाई देती है। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधि का जनादेश केवल उसका व्यक्तिगत जनादेश नहीं रह जाता; वह दल, चुनाव चिन्ह और नेतृत्व से गहराई से जुड़ जाता है। यही कारण है कि चुनाव चिन्ह का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। मतदाता अक्सर व्यक्ति से पहले कमल, पंजा, साइकिल, झाड़ू या अन्य चुनाव चिन्ह को पहचानता है। यदि मतदाता का निर्णय बड़े पैमाने पर दल और नेतृत्व से प्रभावित है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या निर्वाचित सीट को किसी व्यक्ति की निजी राजनीतिक पूंजी माना जा सकता है? सांसद और विधायक भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें जो शक्ति मिली है, वह किसी कॉरपोरेट बोर्ड ने नहीं, बल्कि करोड़ों मतदाताओं ने दी है। इसलिए जब कोई सांसद या विधायक दल बदलता है, तो प्रश्न केवल उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं होता, बल्कि उस जनादेश का भी होता है, जिसे जनता ने उसे सौंपा था। यदि कोई नेता वास्तव में मानता है कि उसकी पुरानी पार्टी अब उसके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो लोकतांत्रिक मर्यादा का तकाजा यह होना चाहिए कि वह पहले इस्तीफा दे और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश मांगे। यदि जनता उसके निर्णय से सहमत होगी, तो वह उसे पुन: चुन लेगी। शायद समय आ गया है कि दल-बदल विरोधी कानून पर नए सिरे से विचार किया जाए। 1985 का कानून उस दौर की राजनीति के लिए बनाया गया था। लेकिन यदि आज चुनाव में दल, चुनाव चिन्ह और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जिस प्रतिनिधि ने किसी दल के चिन्ह पर चुनाव जीता है, उसके दल बदलते ही सीट स्वत: रिक्त मानी जाए और उसे दोबारा जनता के बीच जाना पड़े?

मोदी की जी-7 नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता के मायने

नीरज कुमार दुबे

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने धारदार और दूरदर्शी भाषण से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातों के जरिए भारत की रणनीतिक ताकत और वैश्विक स्वीकार्यता को भी नई ऊंचाई दी। वैश्विक संकट, पश्चिम एशिया का तनाव, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं का संकट तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट और संतुलित सोच ने विश्व नेताओं को प्रभावित किया। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया अब दानदाता और प्राप्तकर्ता की मानसिकता से आगे बढ़कर समान भागीदारी और विश्वास पर आधारित सहयोग की दिशा में आगे बढ़े। यही कारण रहा कि जी-7 सम्मेलन में भारत केवल सहभागी देश नहीं, बल्कि समाधान प्रस्तुत करने वाली शक्ति के रूप में उभरा।

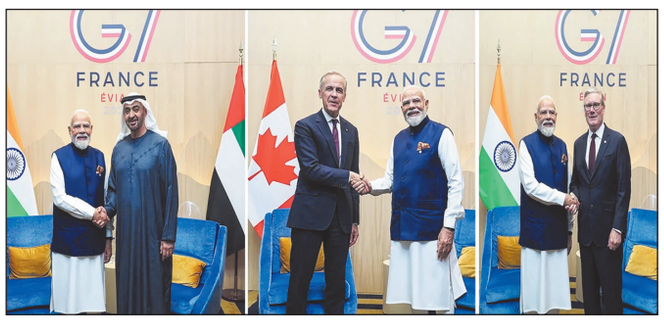

यूएई के साथ द्विपक्षीय वार्ता- प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों का जिक्र करें तो आपको बता दें कि उनकी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ हुई मुलाकात ने भारत और पश्चिम एशिया के बीच बढ़ती रणनीतिक निकटता को और मजबूत किया। वर्ष 2026 में दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी, जो दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और तेजी से मजबूत हो रहे संबंधों का प्रमाण है। बैठक में प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध व्यापारिक आवाजाही की आवश्यकता को रेखांकित किया, क्योंकि यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की धुरी माना जाता है। इस मुलाकात का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह कदम भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए वह पश्चिम एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ बहुआयामी गठजोड़ को मजबूत कर रहा है।

ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन संबंधों को वर्ष 2035 की साझा दृष्टि के अनुरूप और गति देने पर सहमति जताई। व्यापार, हरित ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते सहयोग की समीक्षा की गई। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में भी भारत को बड़ी उपलब्धि मिली, क्योंकि लिवरपूल विश्वविद्यालय द्वारा बेंगलुरु में परिसर स्थापित करने और यॉर्क तथा ब्रिस्टल विश्वविद्यालयों द्वारा मुंबई में अपने परिसरों को स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट में ब्रिटेन की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला की शुरुआत को भविष्य की आर्थिक और सामरिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार बताया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। यह बैठक साफ संकेत देती है कि भारत और ब्रिटेन अब पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर तकनीकी और सामरिक सहयोग के नए युग में प्रवेश कर चुके हैं।

कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता- कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों में नई गर्माहट पैदा की। पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने वाले भारत-कनाडा संबंध अब स्थिरता और सहयोग की नई दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए साझा सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। तरलीकृत प्राकृतिक गैस, रसोई गैस और कोयले से जुड़े व्यापारिक समझौतों में हुई प्रगति पर संतोष जताया गया। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने का साझा लक्ष्य भी तय किया गया। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने के लिए सामान्य सुरक्षा सूचना समझौते पर वार्ता शुरू करने का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और प्रतिभा आदान-प्रदान को लेकर भी दोनों देशों ने नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्रीय संगठन में कनाडा को संवाद सहयोगी बनाने का समर्थन देना भी भारत की व्यापक समुद्री रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कई अन्य द्विपक्षीय वार्ताएं- इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, जर्मनी, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण मुलाकातें कर भारत की वैश्विक कूटनीति को नई मजबूती दी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ बातचीत में व्यापार, निवेश और भविष्य की आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से मुलाकात में दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने पर चर्चा हुई। वहीं केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रुटो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ हुई वार्ता में व्यापार, प्रौद्योगिकी और भविष्य की उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इन मुलाकातों ने साफ कर दिया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को जोड़ने वाला निर्णायक नेतृत्व बन चुका है।

हम आपको यह भी बता दें कि जी-7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सबसे अधिक चर्चा में रहा। उन्होंने साफ कहा कि आज ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि व्यापार और तकनीक का संकीर्ण हितों के लिए दुरुपयोग वैश्विक विश्वास को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए पारदर्शिता और भरोसे पर आधारित वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के मंत्र से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहचान, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी वैश्विक एकजुटता की सबसे बड़ी बाधा है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन, उर्वरक और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़े असर का जिक्र करते हुए उन्होंने ग्लोबल साउथ के गरीब और कमजोर देशों की चिंता उठाई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संकट का बोझ केवल कमजोर देशों पर नहीं छोड़ा जा सकता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को विकासशील देशों की सहायता के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना होगा।

इस सम्मेलन में चीन के बढ़ते निर्यात और वैश्विक बाजारों पर उसके प्रभाव को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। सस्ते उत्पादों के जरिए दुनिया के बाजारों में बढ़ती चीनी पैठ को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता दिखाई दी। इस पूरे विमर्श के बीच भारत एक संतुलित और भरोसेमंद आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ भारत की बात रखी, उसने यह संदेश दिया कि आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक और सामरिक संतुलन में भारत की भूमिका और अधिक निर्णायक होने वाली है। प्रधानमंत्री की इन द्विपक्षीय मुलाकातों से भारत को ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और वैश्विक मंचों पर राजनीतिक समर्थन जैसे कई सामरिक लाभ मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था को दिशा देने वाली जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी सक्रिय और दूरदर्शी कूटनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत अब निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

श्लोक 24 से 26 तक, तथा पद्मपुराण उत्तरखण्ड श्र0 122 श्लोक 25-26- प्रातर्गोवर्धनः पूज्यो द्यूतं रात्रौ समाचत्।

-में स्पष्ट रूप से जुआ खेलने का विधान है।

समाधान

जुआ दो प्रकार का होता है, एक पासे, कौड़ियें, सलाई आदि वस्तुओं की संख्या पर दाव लगाना; दूसरा अन्नादि वस्तुओं के भावी भाव कल्पना करना, तथा मल्लों की शरीरिक गठन के आधार पर हार जीत का अनुमान करना और घुड़दौड़ में घोड़े की चपलता द्वारा तेज दौड़ का अन्दाजा लगाना इत्यादि। मनुस्मृति (6।223) में तथा नारद स्मृति में पहले भेद को जिह्मकारिता (ठगी) के नाम से और दूसरे भेद को समाह्वय (चुनौती) के नाम से याद किया है।

इसमें से वेदादि शास्त्रों ने पहिले प्रकार के जुए को ही निन्दित कहा है, क्योंकि पासे, कौड़ी आदि जड़ वस्तुओं की परतन्त्रता में पड़ कर खेलने वाला अपनी बुद्धि या पौरुष का इसमें कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, वह सर्वथा पराधीन रहता है तथा इससे किसी मानसी शक्ति का भी विकाश नहीं होता। इसीलिये वेद में स्पष्टतया

अक्षैर्मा दीव्य... (ऋग्वेद 10 ।34 ।13)

अर्थात् णशे मत खेल ऐसी आज्ञा दी है।

परन्तु दूसरे प्रकार का जुआ शास्त्रों में पाप नहीं समझा गया, क्योंकि इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है, तथा साहस का भी उत्थान होता है। अतएव याज्ञवल्क्य-स्मृति (व्यवहाराध्याय द्यूत प्रकरण 202) में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि जो द्यूत निषेधक वचन हैं वे सब कूटाक्षदेवन (धोखे से पाशों द्वारा ठगना) विषयक हैं। प्रत्यक्ष में भी संसार भर की समस्त सभ्य गवर्नमेन्टों के कानून में जिह्म (पहिले प्रकार के जुए) को ही अपराध समझा जाता है।

क्रमशः ...

सावित्री की ओर बार-बार देखने पर भी ब्रह्मा क्यों नहीं हुए दोषी? पुराणों में छिपा रहस्य

आशुतोष गर्ग

एक बार वैवस्वत मनु ने भगवान से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी के पांच मुख कैसे उत्पन्न हुए और अपनी ही पुत्री को बार-बार देखने पर भी उन्हें दोष क्यों नहीं लगा? भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, 'जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की इच्छा से सावित्री देवी का ध्यान किया, तो जप करते-करते उनका शरीर पुरुष व स्त्री, दो भागों में विभक्त हो गया। स्त्री सरस्वती कहलाईं और आगे चलकर वही शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उसी रूप को सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कहा जाता है।' उन्होंने आगे बताया कि ब्रह्मा जी ने सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु सावित्री के अद्भुत सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी का चित्त विचलित हो उठा। उनका मन बार-बार सावित्री की ओर आकर्षित होने लगा। सावित्री ने जब अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की, तो सावित्री के रूप को हर दिशा से देखने की इच्छा के कारण ब्रह्मा जी के मुख के दाहिनी ओर एक नया मुख प्रकट हो गया, जिसके गंडस्थल पीले वर्ण के थे। इसके बाद पीछे की ओर एक तीसरा मुख प्रकट हुआ, जिसके होंठ विस्मय से फड़क रहे थे। फिर बाईं ओर एक चौथा मुख प्रकट हुआ, जो कामदेव के बाणों से व्यथित दिखाई देता था। इस प्रकार ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, परंतु सावित्री की ओर बार-बार देखने के कारण ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए जो महान तप किया था, उसका फल नष्ट हो गया। उसी कर्म के परिणामस्वरूप उनके मुख के ऊपर एक पांचवां मुख प्रकट हुआ, जो जटाओं से आच्छादित था। भगवान ब्रह्मा जी ने उस पांचवें मुख को भी स्वीकार कर लिया।

उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने शतरूपा का पाणिग्रहण कर लिया। कालांतर में शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वायंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है। स्वायंभुव ब्रह्मा जी के समान रूप-गुण होने के कारण अधिपुरुष भी कहा गया है। उसी ब्रह्मवंश में आगे सात-सात के क्रम में अनेक मनु उत्पन्न हुए-जैसे स्वारोचिष, औत्तमि आदि, जो सभी भगवान ब्रह्मा के ही समान तेजस्वी और नियम परायण थे। उन्हीं में वर्तमान समय के तुम सातवें, यानी वैवस्वत मनु हो। यह सुनकर मनु ने फिर प्रश्न किया, 'हे भगवन! पुत्री की ओर बार-बार दृष्टि डालना तो अत्यंत निंदनीय कर्म है, फिर ऐसा करने पर भी ब्रह्मा जी दोष के भागी क्यों नहीं हुए? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए।' तब भगवान बोले, 'राजन! रजोगुण से उत्पन्न शतरूपा आदि-सृष्टि दिव्य। जैसे मूल प्रकृति की इंद्रियां इंद्रिय-विषयों से परे हैं, वैसे ही इस शतरूपा का शरीर भी इंद्रियातीत है। वह दिव्य तेज और दिव्य ज्ञान से उत्पन्न हैं, इसलिए सामान्य मनुष्यों की दृष्टि और बुद्धि से उसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी वेदों के अधिष्ठाता हैं, वैसे ही शतरूपा या गायत्री उनके अंग से उत्पन्न मानी गई हैं। इस कारण यह युगल कभी अमूर्त, तो कभी मूर्त रूप में वर्णित किया जाता है। जहां-जहां ब्रह्मा हैं, वहां-वहां सरस्वती या गायत्री भी हैं और जहां-जहां गायत्री हैं, वहां ब्रह्मा। ब्रह्मा वेदस्वरूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी। इसलिए ब्रह्मा जी को सावित्री की ओर दृष्टि करने से कोई दोष नहीं लगा।

अमेरिका-ईरान डील से इजरायल बाहर! समझौते का होगा पालन?

अभिनय आकाश

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर समझौता हो गया है। लेकिन इस समझौते ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मुश्किलों में ला खड़ा कर दिया है। वजह ये है कि जिस जंग में इजरायल सबसे आगे था। उसी जंग को खत्म करने वाले समझौते की शर्तें उसे अभी तक ठीक से पता भी नहीं है। 15 जून की शाम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्ट्रैंडिंग यानी एमओयू पर सहमति बन चुकी थी। समझौते पर डिजीटली साइन हो चुका है और 19 जून को स्विजरलैंड में इसकी औपचारिक साइनिंग होनी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने समझौते के बारे में पूछा तो नेतन्याहू ने माना की इजरायल को अभी तक नहीं पता है कि इस डील में लिखा क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत हो रही है, उससे इजरायल लगभग बाहर ही रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू ने इस छह हफ्ते तक चले इस अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल को एक न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान के खतरे से बचा लिया।

नेतन्याहू ने कहा कि समझौता हो या न हो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। न आज न कल, जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही मेरे जीवन का मिशन है। दरअसल, जंग खत्म होने के तारीखों को लेकर नेतन्याहू को अपने देश के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनकी अपनी सरकार के कुछ लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर जंग रोकने का दबाव बनाया है और कई मामलों में इजरायल को वाशिंगटन की शर्तें

माननी पड़ी हैं। लेकिन नेतन्याहू का दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजरायल के लिए तत्काल खतरा था और अमेरिका के साथ मिलकर उसे खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन इस्राइल ने साफ संकेत दिया है कि वह अपनी सुरक्षा नीति में कोई नरमी नहीं बरतेगा। यरुशलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सागिव स्टीनबर्ग ने कहा है कि इस्राइल हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर अमेरिका की सहमति के बिना भी ईरान पर हमला कर सकता है। मीडिया से बातचीत में स्टीनबर्ग ने कहा कि इस्राइल की उत्तरी सीमा की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमने देखा कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। इस्राइल अब वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता कि कोई भी हमारे नागरिकों की हत्या करे, उन्हें अगवा करने की कोशिश करे। हमारी सीमाओं पर कोई भी आतंकवादी संगठन मौजूद नहीं रह सकता जो किसी सुबह हमला कर दे और लोगों की हत्या या अपहरण कर ले। ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा।

स्टीनबर्ग के अनुसार, इस्राइल का मुख्य लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र में शांति बहाल करना और हिज्बुल्लाह से पैदा होने वाले खतरे को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सुरक्षा खतरा सामने आता है तो इस्राइल कार्रवाई करेगा, भले ही अमेरिका उससे सहमत न हो।

डील के 14 प्वाइंट्स

1. ईरान, लेबनान व अन्य मोर्चों पर युद्ध बंद।
2. अमेरिका की ओर से ईरान की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा।
3. 30 दिन में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म।
4. ईरानी क्षेत्र से अमेरिकी सेनाएं हटेंगी।
5. 30 दिन में होर्मुज को खोला जाएगा।
6. ईरानी तेल, पेट्रो केमिकल और अन्य निर्यातों से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
7. ईरान का निर्यात पर पूर्ण अधिकार।
8. अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देश ईरान के पुनर्निर्माण पैकेज के लिए साढ़े 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे।
9. परमाणु मुद्दे और ईरान पर से पूर्ण प्रतिबंध हटाने के लिए 60 दिन की वार्ता अवधि (नेगोशिएशन पीरियड) होगी।
10. एनएनपीटी के तहत ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का लिखित आश्वासन देगा।
11. वार्ता अवधि में अमेरिका सैन्य जमाव नहीं करेगा और न ही नए प्रतिबंध लगाएगा।
12. वार्ता की शुरुआत में ही अमेरिका ईरान की करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को डीफ्रीज करेगा।
13. वार्ता की शर्तें लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समिति का गठन भी होगा।
14. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद फाइनल एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा करेगा।

इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत को कुचलना चाहता है। लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले कर डील में बाधा पैदा करेगा। ईरान ने परमाणु मुद्दे पर फिलहाल अपने 460 किलो परिष्कृत यूरेनियम को सौंपने का ऐलान नहीं किया है। ईरान ओमान को साथ लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस टैक्स लेने पर अड़ा हुआ है। जबकि अमेरिका यहां पर टैक्स वसूली के विरुद्ध है। अमेरिका और खाड़ी के देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 28 लाख करोड़ के पैकेज पर आसानी से राजी नहीं होंगे। सऊदी अरब और यूएई विरोध करेंगे।

भारत की 55% तेल और 90% एलपीजी की सप्लाई होर्मुज से होती है। अब ये आसान होगी। डील के ऐलान के बाद होर्मुज से गुजरने वाला पहला गैस टैंकर दिशा रहा। कतर से टैंकर भारत पहुंचेगा। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। भारत को आने वाले रेमिटेंस में से 55 अरब डॉलर खाड़ी देशों से ही आता है। ये कुल रेमिटेंस का लगभग 40% है। भारत का खाड़ी देशों को कृषि और खाद्य निर्यात 11.8 अरब डॉलर का है। इनमें से यूएई और सऊदी अरब को सर्वाधिक निर्यात होता है। बासमती, केले और अन्य फल कृषि अर्थव्यवस्था को संबल देंगे।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि सेना लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित समय तक बनी रहेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि लेबनान इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। जब तक इजरायल सेना लेबनान में रहेगी, पूर्ण युद्धविराम संभव नहीं होगा। समझौते के बाद नेतन्याहू की आलोचना बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इजरायल अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया। इसे नेतन्याहू की व्यक्तिगत हार के रूप में देखा जा रहा है। मध्य-वामपंथी डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता याइर गोलान ने इसे कई वर्षों की असफलता का परिणाम बताया।

आज का इतिहास

1716 मुगलों के अजेय होने का भ्रम तोड़ने वाले प्रसिद्ध सिख सैनिक बंदा सिंह बहादुर को बादशाह फरूखसियर के आदेश पर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया।
1843 दास कैपिटल के लेखक और समाजशास्त्री काल मार्क्स ने विवाह किया।
1931 उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म हुआ था।
1945 म्यांमार में लोकतंत्र की अलख जगाने वाली आंग सान सू ची का जन्म।
1947 मशहूर ब्रिटिश-भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जन्म।
1948 सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया।
1968 मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में आर्थिक न्याय के लिए 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया।
1970 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म।
1981 भारत ने अपने भू स्थैतिक उपग्रह ऐपल का सफल प्रक्षेपण किया।
1991 सोवियत संघ ने हंगरी को अपने कब्जे से आजाद किया।
1996 बौद्धिक संपदा क़ानून (आई.पी.आर.) पर चीन एवं सं.रा. अमेरिका में समझौते, प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड एम.सी.सी. की आजीवन सदस्यता से सम्मानित।
1999 कोलोन (जर्मनी) में समूह-8 की शिखर बैठक प्रारम्भ।
2002 पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया।
2003 फ़िनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनेली जाटिनमांकी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
2005 फ़ोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विनफ़े को दुनिया की सौ ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया।
2006 जापान ने उत्तरी कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर चेतावनी दी।
2007 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने सूचना मंत्री के पद से मोहम्मद अली दुर्रानी को हटाया। विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों की सूची में पाकिस्तान को 12वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
2008 उत्तराखण्ड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी व 380 मेगावाट की भैरोंधारी परियोजना को स्थगित किया।
2008 गाजापट्टी में हिंसक संघर्ष रोकने के लिए इस्रायल व हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ।

इंडिया गठबंधन को नयी ऊर्जा की जरूरत

दीपंकर भट्टाचार्य

यह शायद पहला मौका है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग में दिया गया अपना कोई भाषण आम जनता के सामने रखा है। इस भाषण में उन्होंने जिस तरह से एकजुट विपक्षी प्रतिरोध खड़ा करने की आज आवश्यकता बतायी है, वह तारीफ के काबिल है। हालांकि, वास्तव में एक मजबूत और टिकाऊ विपक्षी प्रतिरोध खड़ा करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझावों पर गौर करना भी आवश्यक है। मैंने 'इंडिया' गठबंधन की अब तक की सभी बैठकों में हिस्सा लिया है। इनमें जून, 2023 में पटना में हुई वह शुरुआती बैठक भी शामिल है, जब गठबंधन ने अभी 'इंडिया' नाम भी नहीं अपनाया था।

'इंडिया' गठबंधन की बैठक में दिया गया राहुल गांधी का भाषण जहां एक ओर भरोसा जगाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी पैदा करता है। कांग्रेस की बैठक में उनका यह भाषण भले ही पूरी तरह असरदार लगता, पर 23 अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के उस साझा मंच पर, जो भारत के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है, इस भाषण के कुछ हिस्से मुझे बेसुरे लगे। राहुल गांधी यह याद दिलाते हुए बिल्कुल सही हैं कि 'पूर्ण स्वराज' को आधिकारिक लक्ष्य घोषित करने के बाद कांग्रेस एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरी।

वह प्रस्ताव 1927 के मद्रास अधिवेशन में रखा गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। उसके बाद सचमुच कांग्रेस आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आयी, जिसमें कम्युनिस्ट, समाजवादी और फुले-अंबेडकर-पेरियार की धारा भी अहम हिस्सेदार रही, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 'पूर्ण स्वराज' का विचार सबसे पहले 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में दो कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों, मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद ने रखा था। इसी तरह, 1928 में 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना करके भगत सिंह और उनके साथियों ने भी अपने समाजवादी राजनीतिक लक्ष्य को बेहद साफ और बेबाक ढंग से देश के सामने रखा था।

अगर राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी वैचारिक मुहिम को मजबूती से आगे नहीं बढ़ायेंगे, तो फिर कांग्रेस भी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह ही भारी नुकसान उठायेगी, बल्कि सच तो यह है कि कांग्रेस कई बार ज्यादा ही कमजोर साबित हुई है। भले ही हमारा इतिहास बेहद गौरवशाली रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज 'इंडिया' गठबंधन की किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई वैचारिक ताकत, कवच या सुरक्षा नहीं है, जो उसे अपने-आप बचा सके। एक ओर राहुल गांधी डटकर लड़ने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर, तेलंगाना में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के विवादास्पद अभियान का बचाव करते हुए गर्व के साथ हिटलर का हवाला दे रहे थे।

बेशक, प्रतिरोध पहले से ही जारी है। किसानों ने 2014 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस कराया। किसान विरोधी तीन कृषि कानून भी रद्द हुए। इसी तरह 2019 में नागरिकता संशोधन कानून का एक वर्ग ने विरोध किया। हाल के दिनों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीआर में काम के बढ़ते बोझ और घटती मजदूरी बेहद चिंता पैदा करती है। वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ, वामपंथी छात्र संगठनों-ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-से लेकर सोशल मीडिया पर उभरे मंच तक, छात्र-युवा शिक्षा और परीक्षा की कमियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि ये जन-प्रतिरोध हैं। और जब हम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं, तब उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। जनता के इस साहस और संघर्ष की तुलना राजनीतिक दलों की मौजूदा हालत से कीजिए, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कई राजनीतिक पार्टियां या तो टूट रही हैं या भीतर से बिखरती जा रही हैं। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि प्रतिरोध खड़ा करने की बात करते समय हमें कितना विनम्र होना चाहिए।

'इंडिया' गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह जनसंघर्षों से अपने रिश्ते मजबूत करे, जनता की भावनाओं को ठीक-ठीक समझे, उनकी उम्मीदों को अपनी ताकत बनाये, आदिवासियों की जमीन, जंगल पर उनके अधिकारों एवं उन्हें मिले संवैधानिक संरक्षण को सुनिश्चित करे, न्याय तथा लोकतंत्र के प्रति अपने संकल्पों को दृढ़ता से आगे बढ़ाये तथा साझा प्रतिरोध को और मजबूत बनाये। इस पर विचार करना होगा कि उस जनता के सामने क्या रास्ता बचता है, जिसे ऐसा संविधान विरासत में मिला है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मुद्दों पर एकमात्र जवाब प्रतिरोध ही है- एक ऐसा प्रतिरोध, जो छिटपुट या सिर्फ प्रतीकात्मक न हो, बल्कि लगातार चलने वाला, व्यापक और दृढ़ जनवादी प्रतिरोध हो।

यह सच है कि 'भारत जोड़ो यात्रा' का संदेश और बीच-बीच में आये हौसला बढ़ाने वाले कुछ चुनावी नतीजे-चाहे वह 2020 में बिहार में भाजपा की मामूली जीत हो या पश्चिम बंगाल (2021) और कर्नाटक (2023) में उसकी हार-इन सबने मिलकर ही 2023 में 'इंडिया' गठबंधन के उभरने के लिए एक मुफीद जमीन तैयार की। जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय लोक दल के इससे बाहर निकलने और पश्चिम बंगाल, केरल तथा पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी तालमेल न होने के बावजूद, 2024 में 'इंडिया' गठबंधन ने रणनीतिक रूप से देश के लोगों में उम्मीदें पैदा कीं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ हद तक बिहार के नतीजों ने 'इंडिया' गठबंधन की ताकत दिखायी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंची और पूरे गठबंधन का आंकड़ा 234 सीटों तक जा पहुंचा।इसके बाद से, एक के बाद एक चुनावी झटके-2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा तथा 2025 में दिल्ली में हार-ने 'इंडिया' गठबंधन की ताकत और असर को कमजोर किया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे में 'इंडिया' गठबंधन को अब एक नयी ऊर्जा और दिशा की बहुत आवश्यकता है। इस कठिन दौर में राहुल गांधी की दोहरी जिम्मेदारी है-एक तरफ कांग्रेस में नयी जान फूंकना और दूसरी तरफ गठबंधन के व्यापक मंच को मजबूत करना। यह तभी हो सकता है, जब अलग-अलग इतिहास और विचारधारा वाले सभी दलों के बीच आपसी सम्मान, भरोसा और तालमेल बना रहे।

पाकिस्तान के 'रणनीतिक महत्व' को कमतर समझने के खतरे

लै. ज. सैयद अता हसनैन

पाकिस्तान एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन निराशाजनक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में अशांति साफ दिखाई दे रही है, वहीं अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष एक स्थायी सुरक्षा चुनौती बन गया है। फिर भी, पाकिस्तान पतन के कगार पर खड़ा राष्ट्र नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लिए पाकिस्तान को एक महत्वहीन रणनीतिक चिंता के रूप में देखना अनुचित होगा। भौगोलिक दृष्टि से ही पाकिस्तान विश्व के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में से एक है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के मिलन बिंदू पर स्थित होने के कारण, यह देश आंतरिक अव्यवस्थाओं के दुष्परिणामों से बार-बार बचा रहा है। शीत युद्ध के दौरान पश्चिम के लिए इसका महत्व था, अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के दौरान यह अपरिहार्य बन गया, 9/11 के बाद इसने फिर से केंद्रीय भूमिका निभाई और अब, ईरान और अफगानिस्तान में नई अनिश्चितता और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, यह एक बार फिर प्रासंगिक हो गया है। भारत को अब पाकिस्तान की घरेलू अशांति से नहीं, बल्कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है, उससे चिंतित होना चाहिए। महज 16 महीनों के भीतर पाकिस्तान द्वारा चीन समर्थित 6 निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण की खबरों की हमारे रणनीतिक हलकों में गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह मामूली आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षमता में एक संरचनात्मक छलांग है। खुफिया, निगरानी और टोही तंत्र आधुनिक युद्ध में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आज वास्तविक समय में युद्धक्षेत्र की जानकारी, जमीनी स्तर पर सैन्य बलों के अनुपात के साथ-साथ परिचालन सफलता को भी निर्धारित करती है, खासकर बहु-क्षेत्रीय अभियानों में। इससे भी अधिक ड्क्षचताजनक बात यह है कि इस उभरते तंत्र के कुछ हिस्सों को भारत के उत्तरी परिचालन क्षेत्र की बार-बार और केंद्रित निगरानी के लिए डिजाइन किया गया प्रतीत होता है। पाकिस्तान की विकसित होती साइबर क्षमता पर भी गहन और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षों तक, साइबर टकराव काफी हद तक छिटपुट हमलों और मामूली व्यवधान तक ही सीमित रहा। वह दौर अब बदल गया है। पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान अब साइबर क्षमता को एक ऐसे असममित उपकरण के रूप में देखता है, जो पारंपरिक कमियों की भरपाई करने में सक्षम है। चीनी तकनीकी सहायता के साथ मिलकर, साइबर अभियान इस्लामाबाद को संकट के समय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सूचना प्रणालियों और जनविश्वास को निशाना बनाने के लिए एक कम लागत वाला लेकिन अत्यधिक विघटनकारी उपकरण प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र अब निर्णायक मोर्चे बन गए हैं, जहां पारंपरिक सैन्य संघर्ष शुरू होने से बहुत पहले ही रणनीतिक लाभ को आकार दिया जा सकता है। अमरीका अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान युद्ध के दौरान जैसी नजरों से नहीं देखता लेकिन इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय संकट गहराने पर वाशिंगटन समय-समय पर पाकिस्तान की ओर रुख करता है। साथ ही, पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध कायम रखने का सावधानीपूर्वक प्रयास कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया में संतुलन और स्पष्टता की जरूरत है। पाकिस्तान को केवल इसलिए एक मामूली खतरा नहीं माना जा सकता क्योंकि हाल के वर्षों में भारत द्वारा उसे लगातार सैन्य रूप से मिली हार से उसकी कमजोर क्षमता की धारणा बन गई है। भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजन में नागरिक-सैन्य एकीकरण को गति देनी चाहिए। इस क्षेत्र में पहले से ही काफी प्रगति हो रही है। भारत के हितों के विरुद्ध रणनीतिक सांझेदारियों का दुरुपयोग करने की पाकिस्तान की क्षमता को लगातार कमजोर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

संयुक्त शक्ति बन कर खड़े होते चार मुख्यमंत्री

प्रभु चावला

पिछले सप्ताह नीति आयोग की बैठक में चार मुख्यमंत्री याचक बनकर नहीं, संगठित और समन्वित शक्ति के रूप में पहुंचे। केरल के वीडी सतीशन, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के जोसेफ विजय ने एक साथ बैठक में प्रवेश किया और बैठक से निकलते हुए इन चारों ने भारतीय संघवाद की परिभाषा बदल दी। इन चार राज्यों की संयुक्त शक्ति की अनदेखी करना असंभव है। लोकसभा में इनके पास 104 सीटें हैं। ये राज्य देश की जीडीपी का लगभग 26 फीसदी उत्पन्न करते हैं और प्रत्यक्ष कर राजस्व में करीब 30 फीसदी का योगदान देते हैं। इनमें से किसी भी राज्य की सरकार केंद्र की सत्तारूढ़ व्यवस्था का हिस्सा नहीं है।

ये दिल्ली अपने साथ शिकायतों की सूची नहीं, संरचनात्मक समस्याओं का विश्लेषण लेकर गये थे। विपक्षी राजनीति ने दशकों से शोर को शक्ति समझने की भूल की है। दक्षिण के इन चार नेताओं ने पहली बैठक में ही यह परंपरा तोड़ दी। वैचारिक रूप से एकजुट समूह के रूप में सामने आकर इन्होंने दक्षिणी एकजुटता को प्रभावशाली बना दिया। इन्होंने राष्ट्रीय मंच पर जो मुद्दा रखा है, वह वास्तविक है और संवैधानिक व्यवस्था की उपज भी। दक्षिणी राज्यों ने हर प्रशासनिक और विकास मानक पर आदर्श संघीय नागरिकों-सा व्यवहार किया है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को तब नियंत्रित किया, जब यह राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी था।

शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से इन्होंने मानव संसाधन की मजबूत नींव तैयार कीं और निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं विकसित कीं। पर अगली जनगणना के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में इन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी मिलने की आशंका है। इन्हें लगता है कि सुशासन और विकास को दंडित किया जा रहा है, जबकि जनसंख्या विस्तार को पुरस्कृत किया जा रहा है। छप्पन वर्षीय रेवंत रेड्डी ने इस विरोधाभास को सबसे प्रभावी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति दी है। इनका प्रस्तावित मिश्रित फॉर्मूला, जिसमें आधी सीटें आबादी के आधार पर और आधी आर्थिक योगदान के आधार पर आवंटित की जायें, कोई नया सिद्धांत नहीं। यह केवल उस मान्यता को लोकसभा की संरचना तक ले जाता है, जो अभी बजटीय गणनाओं में मौजूद है। इस तरह इन्होंने एक क्षेत्रीय चिंता को संवैधानिक प्रश्न में बदल दिया है, जिसका सामना किसी भी गंभीर संघीय लोकतंत्र को करना ही होगा।

रेवंत रेड्डी परिसीमन बहस का राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं और उनके पास इसे लंबे समय तक जीवित रखने की ऊर्जा और क्षमता भी है। बासठ वर्षीय वीडी सतीशन इस समूह के बौद्धिक और नैतिक स्तंभ हैं। सक्रिय वकील और छह बार विधायक रहे सतीशन ने केरल में कांग्रेस का पुनर्निर्माण धैर्यपूर्ण और सिद्धांतनिष्ठ कार्य से किया। उनके पास स्वच्छ शासन का प्रमाणित अनुभव है। जबकि चौंसठ वर्षीय डीके शिवकुमार इस समूह की अनिवार्य संगठनात्मक शक्ति हैं। आठ बार विधायक रह चुके शिवकुमार बूथ स्तर की राजनीति और गठबंधन गणित पर अद्वितीय पकड़ रखते हैं। इन्होंने कर्नाटक में लगभग समाप्तप्राय स्थिति से कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और अस्तित्व की लड़ाई को स्थिर शासन में बदला। कर्नाटक केवल एक और दक्षिणी राज्य नहीं, बल्कि पूरे प्रायद्वीप का भौतिक व राजनीतिक सेतु है। जो भी राजनीतिक गठबंधन राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करना चाहता है, उसे इस द्वार से होकर गुजरना होगा।

इक्यावन वर्षीय जोसेफ विजय इस समूह का सबसे परिवर्तनकारी तत्व हैं। इन्होंने वंशवादी राजनीति तथा स्थापित दल में लंबी राजनीतिक प्रशिक्षण प्रक्रिया के बगैर और बिना उस वैचारिक ढांचे के राजनीति में प्रवेश किया, जो आमतौर पर तमिलनाडु की राजनीति को आकार देता है। इन्होंने अपनी सांस्कृतिक लोकप्रियता को ऐसे बहुमत में बदला, जो अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े संसदीय प्रतिनिधित्व वाले राज्य पर शासन करता है। अपने पहले कार्यकाल में नीति आयोग की बैठक में इनकी उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति तमिलनाडु की पारंपरिक दूरी अब बदल रही है।

विजय के पास विभिन्न समुदायों में फैला ऐसा समर्थन आधार है, जिसे पारंपरिक राजनीतिक श्रेणियों में आसानी से नहीं बांधा जा सकता। ये चारों एक दिशा में काम करें, तो वह चीज पैदा कर सकते हैं, जिसे भारतीय विपक्षी राजनीति करने में बार-बार विफल रही है। भाजपा की संगठनात्मक उपस्थिति दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में अब भी सीमित है। तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में उसकी चुनावी संभावनाएं संरचनात्मक रूप से बाधित हैं। केवल कर्नाटक ही वास्तविक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। यह असमानता इस चौकड़ी को वह रणनीतिक स्वतंत्रता देती है, जो हिंदी पट्टी के विपक्षी नेताओं को शायद ही प्राप्त हो। फिर भी इन चारों की वास्तविक प्रतिद्वंद्वी भाजपा नहीं है। क्षेत्रीय गठबंधनों का इतिहास बताता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, राज्यों के परस्पर विरोधी हित और तात्कालिक राजनीतिक लाभ अक्सर उन्हें तोड़ देते हैं। जाहिर है, प्रभावशाली एकजुटता को स्थायित्व में बदलना चुनाव जीतने से अधिक कठिन कार्य है। इतिहास में सफलता की तुलना में असफलता के उदाहरण अधिक हैं।

फिर भी इस बार परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल हैं। इस समूह की आर्थिक शक्ति और संसदीय संख्या इन चारों को वह राजनीतिक प्रभाव प्रदान करती है, जो केवल भावनाओं से संभव नहीं होता। परिसीमन का प्रश्न इन्हें एक स्थायी संवैधानिक मुद्दा देता है, जिसके इर्द-गिर्द समय के साथ समन्वय मजबूत हो सकता है। चूंकि इन चारों में से कोई भी राष्ट्रीय राजनीति की पारंपरिक चरम आयु से आगे नहीं निकला है, ऐसे में, इस परियोजना को अगले दशक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक ऊर्जा उपलब्ध है। यदि यह अनुशासन बना रहता है, तो इसका असर अगले चुनावी चक्र से कहीं आगे तक जायेगा। इतनी आर्थिक और संसदीय शक्ति वाला दक्षिणी गठबंधन समय के साथ संघवाद की शर्तों पर पुनर्विचार करवाने की स्थिति में पहुंच सकता है। वैसे में, राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति स्थायी रूप से बदल सकती है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और 'एक दल का प्रभुत्व' जैसी अवधारणाओं की जगह ऐसी राजनीति ले सकती है, जिसमें केंद्र में शासन करने की आकांक्षा रखने वाली किसी भी पार्टी या गठबंधन को दक्षिणी राज्यों की शक्ति को स्वीकार करना पड़े। यह इस पर निर्भर करेगा कि ये चार नेता आगे क्या करते हैं। दक्षिण भारत को ऐसे नेता मिले हैं, जो दांव पर लगे मुद्दों की गंभीरता को समझते दिखाई देते हैं। राजनीतिक शक्ति का केंद्र धीरे-धीरे स्थानांतरित हो रहा है-आबादी के संयोग से नहीं, बल्कि सुनियोजित संगठन और रणनीति के कारण। बहस बदल चुकी है। संभव है कि सत्ता की संरचना भी जल्द ही उसके पीछे-पीछे बदल जाये।

गुमनाम पार्टी में क्यों शामिल हुए टीएमसी के नामी सांसद?

नीरज कुमार दुबे

तृणमूल कांग्रेस में उठी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई दे सकती है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अचानक एक लगभग गुमनाम दल नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग समूह के तौर पर मान्यता तथा सदन में अलग बैठने की मांग कर डाली। इस घटनाक्रम ने केवल बंगाल की राजनीति को नहीं हिलाया, बल्कि दलबदल कानून, विपक्ष की एकजुटता और संसद की शक्ति संतुलन की बहस को भी फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है, उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग नगण्य रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने चार उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरकार तीन सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया। पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि वे कई जगह नोटा से थोड़ा ही आगे निकल सके। त्रिपुरा की चावमानु सीट पर पार्टी उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा को केवल 536 वोट मिले, जबकि नोटा को 500 वोट प्राप्त हुए। कैलाशहर सीट पर पार्टी को मात्र 286 वोट मिले। कुल मिलाकर दो सीटों पर एनसीपीआई को सिर्फ 822 वोट हासिल हुए थे।

खास बात यह भी है कि इस पार्टी का चुनाव चिह्न 'पेन की निब' है और इसने नारा दिया था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलबदलुओं को नकारें। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि अब वही दल देश के सबसे चर्चित दलबदल का मंच बन गया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। बागी सांसदों का मकसद सीधे भाजपा में जाना नहीं, बल्कि पहले एक अलग राजनीतिक पहचान बनाकर दलबदल कानून से बचना माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची के

तहत यदि किसी दल के दो तिहाई विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बागी गुट खुद को असली तृणमूल साबित करने की जमीन तैयार कर रहा है।

तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने साफ कहा है कि अभी उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है, लेकिन संसद का अगला सत्र शुरू होने पर वह तृणमूल नाम और पहचान पर दावा करेंगे। उनका कहना है कि दो तिहाई सांसद उनके साथ हैं, इसलिए वास्तविक राजनीतिक अधिकार भी उसी गुट के पास होना चाहिए। दूसरी ओर, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट वाले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल विधायी दल का टूटना पर्याप्त नहीं होता, मूल राजनीतिक दल का विलय भी जरूरी है।

देखा जाये तो यही वह बिंदु है जहां यह लड़ाई केवल संख्या की नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक व्याख्या की बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी सर्वोपरि है, सांसद नहीं। जबकि बागी गुट संख्या बल के आधार पर वैधता चाहता है। इस टकराव का अंतिम फैसला अब अदालत और लोकसभा अध्यक्ष की व्याख्या पर निर्भर करेगा।

हम आपको यह भी बता दें कि इस घटनाक्रम की तुलना 2016 के अरुणाचल प्रदेश संकट से भी की जा रही है। तब कांग्रेस के अधिकांश विधायक पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में गए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। उसी रास्ते ने भाजपा को पूर्वोत्तर में पहली पूर्ण सरकार दी थी। अब तृणमूल के भीतर भी वैसी ही पटकथा दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति पर लगा है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। बंगाल में भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और अब यदि लोकसभा में पार्टी का बड़ा हिस्सा अलग खड़ा हो जाता है, तो विपक्षी राजनीति में ममता की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ सकती है। खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी एकता की राजनीति पहले ही बिखराव का शिकार है।

दूसरी ओर, भाजपा के लिए यह घटनाक्रम अप्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। बागी सांसदों ने पहले ही राजग को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। यदि यह समीकरण आगे बढ़ता है, तो संसद में सत्ता पक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

सबसे तीखी चोट हालांकि राजनीति की नैतिकता पर पड़ती दिखाई देती है। जिस दल ने दलबदलुओं को नकारने का नारा दिया था, वही अब दलबदल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। यह भारतीय राजनीति का वह चेहरा है, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व संख्या, सत्ता और कानूनी चालों का रह गया है। छोटे दल अब केवल चुनाव लड़ने के मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्जन्म के औजार बनते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की यह टूटन आने वाले दिनों में केवल बंगाल की राजनीति नहीं बदलेगी, बल्कि यह तय करेगी कि देश में दलबदल कानून की असली ताकत कितनी बची है। संसद, अदालत और चुनाव आयोग, तीनों की अग्निपरीक्षा अब शुरू हो चुकी है। उधर, एनसीपीआई पार्टी के कार्यालय के बाहर इन दिनों कौतूहल के साथ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आसपास के लोगों का तो यहां तक कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहां से कोई पार्टी चल रही है।

नेपाल के साथ रिश्तों को गति देने की कोशिश

शोभना जैन

नेपाल के साथ पिछले कुछ सालों से भारत के संबंध असहजता के दौर से गुजरते रहे हैं। नेपाल में 'जेन-जी' के जनआंदोलन के बाद, गत मार्च में प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। फिर वहां के उच्चस्तरीय नेताओं की भारत यात्रा के बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने हाल ही में भारत की यात्रा की, जिसे संबंधों को सहज करने की नई कोशिश माना जा सकता है। नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत के साथ सीमा विवाद संबंधित विवादास्पद और अस्वीकार्य टिप्पणियों के बाद नेपाल द्वारा भारत के साथ साझा विरासत वाले संबंधों को आगे बढ़ाते हुए रिश्तों को सहज बनाने की ताजा कोशिश के लिए मौजूदा वक्त भी अनुकूल है। हां, यहां अहम बात यह है कि नेपाल यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती के साथ भी संतुलन बना रहे। विदेश मंत्री खनाल भारत के फौरन बाद अगले सप्ताह चीन दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नेपाली विदेश मंत्री की इस यात्रा को नेपाल की भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है कि मौजूदा दौर में नेपाल भारत और चीन, दोनों ही देशों से दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाहता है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नेपाल अपनी विदेश नीति में लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत पर कायम रहेगा। वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में नेपाल सरकार ने कहा है कि वह पारस्परिक लाभ, राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभु हितों के आधार पर संतुलित विदेश संबंधों को मजबूत करेगी। जहां तक बात नेपाली प्रधानमंत्री शाह की विवादास्पद टिप्पणी की है तो दिल्ली से लौटने पर खनाल ने अपनी संसद में

दिए गए बयान में कहा कि नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए न तो तीसरे पक्ष की मदद मांगी है और न ही वह ऐसी किसी बात का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री शाह ने मध्यस्थता की बात नहीं की थी बल्कि यह राय जाहिर की थी कि सुगौली संधि के दौर को ले कर अगर किसी के पास कोई 'ऐतिहासिक उल्लेख' उपलब्ध हैं तो वे इस मामले से सम्बद्ध तकनीकी प्रक्रिया के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इस बार में उपजे तमाम विवादों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की तकनीकी टीमें सीमा के खंभों को चिन्हित करने सहित सीमा पर कब्जे को लेकर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और यह प्रक्रिया विवादास्पद बिंदुओं को हल करने के लिए कारगर ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने स्पष्ट रूप से यह विचार रखा है कि सीमा से संबंधित मुद्दों को कूटनीति और मौजूदा तंत्र के माध्यम से हल किया जा सकता है। बहरहाल, दोनों देश संबंधों की नजाकत समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा और एक-दूसरे के राष्ट्रीय हितों में तीसरे पक्ष के शामिल होने की कोई संभावना नहीं होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों के फलने-फूलने की पहली शर्त होती है।

क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी।

संख्या पढकर चौंक गए परंतु यह सत्य है, शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। वास्तव में उनकी 16,108 पत्नियां थी। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुविवाह प्रथा बहुत लोकप्रिय थी, फिर भी 16,108 की संख्या बहुत अधिक लगती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कहानियाँ हैं जो काफी रोचक हैं। भगवान कृष्ण अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं जिनकी रोचक कहानियाँ हमारे मन में कुतूहल उत्पन्न करती है। राधा के साथ उनका आत्मिक प्रेम, आठ सुन्दर राजकुमारियों से विवाह तथा फिर भी 16,000 और अधिक पत्नियां निश्चित रूप से हमें आश्चर्यचकित कर यह जानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण होगा। यदि हम शास्त्रों में देखें तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण से राधा से कभी भी विवाह नहीं किया था।

क्यूं पड गया श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला परन्तु उन्होंने आठ महिलाओं से शादी की। उनकी आठ पत्नियों के नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नाजिती, भद्रा और लक्ष्मणा थे। उनमें से सत्यभामा और रुक्मिणी प्रसिद्ध हैं। अब 16,000 पत्नियों की कहानी की ओर बढते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक चमत्कारी राजा थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई न कोई कारण था। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि 16,108 पत्नियां कृष्ण लीला का एक हिस्सा थी। अत: ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि भगवान कृष्ण को 16,000 महिलाओं से विवाह करना पडा आइए देखें।

महाभारत से जुडे कुछ रोचक रहस्य नरकासुर की कहानी नरकासुर प्रग्ज्योतिषा का राजा था। यह स्थान अब असम के नाम से जाना जाता है। वह विष्णु के सूअर अवतार वराह और पृथ्वी की देवी भूमि देवी का पुत्र था। भूमि का पुत्र होने के कारण उसे भौम या भौमासुर भी कहा जाता था। उसने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों विश्व पर कब्जा कर लिया था। उसने पृथ्वी पर जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की थी उन देशों की राजकुमारियों को कैद कर लिया था।

स्वर्ग में उसने स्वर्ग और देवों के देव इंद्रदेव की मां अदिति के कान के बाले (इयररिंग) चुराए। पाताल में उसने पानी के देवता वरुण का शाही छाता चुरा लिया। उसने राजकुमारियों को एक पर्वत पर बंदी बना कर रखा। इसी दौरान इंद्र ने अदिति के कान के बाले वापस लाने तथा विश्व को इस राक्षस की क्रूरता से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण से नरकासुर के साथ युद्ध करने की याचना की। अत: भगवान कृष्ण ने राक्षस का वध कर दिया। लूट का माल नरकासुर की मृत्यु के पश्चात भूमि देवी ने सभी चुराई हुई चीजें कृष्ण को वापस कर दीं जिसमें 16,000 महिलायें भी शामिल थी। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया परन्तु उन महिलाओं से इसका पालन नहीं किया।

सामाजिक कलंक प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था तो राजा के परास्त होने के बाद भी उस महिला को राज्य में वापस नहीं लिया जाता था। उन्हें एक कलंकित और शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पडता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उन्हें स्पर्श किया है। नरकासुर की कैद में रहने वाली 16,108 महिलाओं को भी यह सहन करना पडा। अत: उन सभी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। 16,108 पत्नियां अत: भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया। भागवत पुराण में विवाह के बाद कृष्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बताया गया है। प्रत्येक पत्नी को एक घर और सौ दासियाँ दी गयी थीं। कृष्ण ने स्वयं को कई रूपों में बाँट लेते थे तथा इस प्रकार रात में प्रत्येक पत्नी के साथ रहते थे। सुबह उनके सभी रूप मिलकर कृष्ण बन जाते और वे द्वारका के राजा रूप में आ जाते। कृष्ण की प्रत्येक पत्नी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहला कर, सजा कर, पंखा झलकर, उन्हें उपहार और फूलों की माला देकर उनकी पूजा करती थी।

चमत्कारी राजा एक कथा के अनुसार एक बार उपद्रवी मुनि नारद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी पत्नियों में से एक पत्नी उन्हें दे दें क्योंकि वे कुंवारें हैं। कृष्ण ने उनसे कहा कि आप किसी भी पत्नी को उस समय जीत कर दिखाएँ जब मैं (कृष्ण) उनके साथ न रहूँ। नारद कृष्ण की सभी 16,108 पत्नियों के घर गए परन्तु सभी घरों में कृष्ण उपस्थित थे। इस पारकर नारद कुवारें रह गए। इस घटना को देखकर नारद आश्वस्त हो गए कि भगवान कृष्ण के रूप में एक देवत्व था, एक पूर्ण और विविध आकार वाली अभिव्यक्ति जो एक ही समय में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ का आनंद उठा रही थी। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को सर्वशक्तिमान माना जाता है जो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं जैसे वे अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे।

कुंडली में मांगलिक दोष निवारण के उपाय

मांगलिक दोष क्या है।

जन्मपत्री की कुंडली में 12 स्थान होते हैं। इनमे से यदि पहले, दुसरे, चौथे, सातवे, आठवे और बारहवें स्थान में मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष वाले व्यक्ति पर मंगल गृह की बुरी छायां होती है। यह प्रभाव शादी के समय बहुत मायने रखता है क्यों कि शादी के समय कुंडली मिलान का यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शादी से पहले व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष को देखना और इसका निवारण करना जरूरी है।

मांगलिक दोष के लक्षण

1. स्त्री और पुरुष दोनों में मांगलिक दोष हो सकता है।

2. मंगल को उग्रता वाला गृह माना जाता है इसलिए मांगलिक दोष वाले लोगों का स्वाभाव गर्म माना जाता है।

3. मांगलिक लोगों में बहुत गर्म और उग्र ऊर्जा होता है जिसका यदि सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह कुछ ना कुछ गलत हो सकता है।

4. मांगलिक दोष के कारण शादी में देरी होती है।

5.मंगल दोष के कारण शादी में कलह और तनाव रहता है।

6. दो मांगलिक लोगों का आपस में विवाह करने से इसका बुरा प्रभाव दूर होता है।

7. ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने पिछले जन्म में अपने पार्टनर के साथ बुरा किया उनमें यह दोष पाया जाता है।

मंगल कब समस्या पैदा करता है

1.यदि मंगल पहले स्थान में है तो शादी के बाद विवाद और हिंसा की सम्भावना रहती है।

2. जब मंगल दुसरे स्थान में रहता है तो व्यक्ति के परिवार के कारण उसका विवाह और नौकरी पेशा प्रभावित होता है।

3. जब मंगल चौथे स्थान में रहता है तो व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर सफलता प्राप्त नहीं करता है और लगातार जॉब बदलता है।

4. यदि मंगल सातवे स्थान में होता है तो उसका स्वाभाव उग्र होता है, जिसके कारण वह अपने परिवार से भी मधुर सम्बन्ध नहीं रख पाता है।

5. यदि मंगल आठवे स्थान में होता है तो वह व्यक्ति परिवारजनों द्वारा अलग कर दिया जाता है और जायदाद से बेदखल हो जाता है।

6. जब मंगल दसवे स्थान में होता है तो व्यक्ति को दिमाग से सम्बंधित समस्याएं होती है साथ ही इससे दुश्मन पैदा होना या आर्थिक नुकसान जैसी चीजें भी हो सकती हैं।

मांगलिक दोष निवारण के उपाय

1. दो मांगलिक लोगों का विवाह करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है।

2. कुम्भ विवाह भी इसका एक समाधान है। इस विवाह में व्यक्ति को शादी से पूर्व किसी पेड से या कलश से विवाह करना पडता है।

3. मंगलवार का व्रत करने से भी इसका बुरा प्रभाव कम होता है। इस व्रत में मांगलिक लोगों को तूर दाल ही खानी होती है।

4. मंगलवार को नवग्रह मन्त्र या हनुमान चालीसा का जाप करने से भी मांगलिक दोष का असर कम होता है।

5. मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना भी मंगल दोष के निवारण का अच्छा उपाय है।

6. ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक दोष वाले लोगों को लाल मूंगा जडित सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करनी चाहिए।

7. मांगलिक लोगों को 28 साल की उम्र के बाद शादी करने की सलाह दी जाती है क्यों कि उम्र के अनुसार दोष का असर भी कम हो जाता है।

हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व

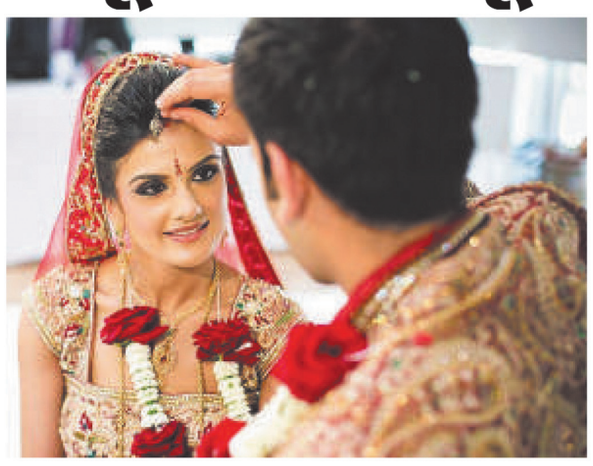

आमतौर पर सिंदूर को हिंदू महिलाओं द्वारा लगाया जाता है तथा इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में छुपा है। सिंदूर, एक स्त्री के विवाहित होने की निशानी है तथा इसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते लगाती हैं। इसे माथे पर बालों के बीच में लगाया जाता है।

हिंदू धर्म में, इसे लगाने का हक केवल विवाहित महिलाओं को दिया गया है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, देवी पार्वती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी जिसके कारण सिंदूर को देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अत:, माना जाता है कि जो महिला अपने माथे पर सिंदूर धारण करती है, देवी पार्वती का हाथ उसके सर पर सदैव बना रहता है तथा देवी पार्वती हर समय उसके पति की रक्षा करती है।

भारतीय महिलाएं क्यूं पहनती हैं नोज रिंग इसके अलावा सिंदूर धारण करने के कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। तो चलें, उन महत्वपूर्ण कारणों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं।

1 ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, मेष राशि का स्थान माथे पर होता है। मंगल, मेष राशि का स्वामी ग्रह है और क्योंकि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, इसे शुभ माना जाता है। अत: इसे सौभाग्य का संकेत भी माना जाता है।

2 सिंदूर को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति एक पत्नी को किसी भी मुश्किल घडी में अपने पति की रक्षा करने में मदद करती है।

3 उत्तर भारत में नवरात्रि व संक्राति के त्योहारों पर विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना अत्यंत अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि सिंदूर धार्मिक कारणों की वजह से भी बहुत महत्व रखता है। हिंदू परंपराओं के पीछे छुपा हुआ है ये विज्ञान

4 सिंदूर लगाने का एक और दिलचस्प कारण भी है। सिंदूर को धातु पारे के साथ हल्दी व चूने के मिश्रण से तैयार किया जाता है। पारा रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है एवं महिलाओं की यौन इच्छा को सक्रिय करता है। जिसके कारण इसमें एक शारीरिक महत्व भी शामिल हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमारी भावनाओं के केन्द्र, पिट्यूटरी ग्रंथ पर लगाना चाहिए।

धन का संचय उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो

बात उस समय की है जब गुरु नानक देव लाहौर यात्रा पर थे। वह एक अजीब नियम था। वो यह कि जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति वह अपने घर के ऊपर उतने ही झंडे लगाता था।लाहौर में दुनीचंद्र के पास 20 करोड रुपए की संपत्ति थी। इसलिए उसके घर की छत पर 20 झंडे फ्हरा रहे थे। दुनीचंद्र को पता चला कि गुरु नानक जी लाहौर आए हैं तो वो उनसे मिलने गया। दुनीचंद्र ने गुरुनानक जी से सेवा का अवसर मांगा। गुरु नानक जी ने उसे एक सुई देते हुए कहा, इसे ले जाइए और अगले जन्म में मुझे वापस कीजिएगा। दुनीचंद्र ने सुई ले ली। लेकिन उसने सोचा कि अगले जन्म में यह सुई मैं कैसे ले जा सकूंगा। वह वापस गुरु नानक जी के पास गया और उसने कहा, मरने के बाद में यह सुई कैसे ले जा सकता हूं। तब गुरु नानक जी ने कहा, जब तुम एक सुई अपने अगले जन्म में नहीं ले जा सकते तो इतनी सारी संपत्ति कैसे ले जा सकोगे। दुनीचंद्र ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं।

राहु दोष दूर करने के आध्यात्मिक उपाय

हिंदु धर्म में राहु और केतू दो ग्रह हैं जिन्हे दोष के रूप में जाना जाता है। राहु और केतू, एक ही असुर का नाम है जिसने अमृत मंथन के दौरान छल से अमृत पी लिया था और जब उसने आधा अमृत पी लिया तब पता चला कि वह असुर है तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। वह मरा नहीं, लेकिन सिर और धड दो हिस्सों में बंट गया, जिसे राहु-केतु के नाम से जाना गया। ये एक ग्रह बन गए जो लोगों की कुंडली में दोष माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इन्हे दूर करने के कई उपाय हैं, जिन्हे लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते है कि जीवन से राहु-केतु का दोष किस प्रकार दूर करना है। तो इन आध्यात्मिक उपायों को जानें।

राहु दोष दूर करने के आध्यात्मिक उपाय

प्रत्येक शनिवार शाकाहारी भोजन करें: राहु और केतू दोष ग्रह है। इसके लिए आपको शनिवार को पूजा क रनी चाहिए और इस दिन पूर्णत: शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए।

भगवान शिव की पूजा करें: अगर आपकी कुंडली में राहु-केतू का दोष है तो भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव, राहु-केतू और शनि के दोषों का निवारण करते है। आप प्रतिदिन 21 बार ओउम् नम: शिवाय का जाप करें। राहु शांति पूजा का प्रदर्शन करें: राहु और केतू के दोषों को शांत करने के लिए आप राहु शांति पूजा का प्रदर्शन करें। इस पूजा को आप घर पर आयोजित करवाएं, इससे आपके घर में सुख और शांति भी आएगी। श्रीकलाहस्ती मंदिर के दर्शन करें: श्रीकला हस्ती मंदिर आंध्रप्रदेश में स्थित है। जिन लोगों के जीवन में राहु-केतू दोष है वह इस मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। साल में भारी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते है।

दान: राहु-केतू दोष होने पर आप शनिवार को सरसों का तेल दान करें, गेहूं, नारियल, केला आदि को दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। इससे आपको जीवन में सुकून और खुशी मिलेगी और यह ग्रह दोष भी शांत हो जाएगा।

भोले के भैरव रूप के स्मरण से दूर होते हैं कष्ट

-**पहली** फरवरी को है कालाष्टमी

-रात्रि को जागरण कर शिव एवं माता पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करें

-ब्रहमा के अपमानित करने पर शिव भगवान ने धारण किया था रौद्र रूप

कालाष्टमी का हिंदू धर्म में बडा महत्वपूर्ण स्थान है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शिव, भैरव रूप में प्रकट हुए थे। कालाष्टमी का व्रत इसी उपलक्ष्य में किया जाता है। कालाष्टमी को 'भैरवाष्टमी' के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भैरव रूप के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव की पूजा व उपासना से मनोवांछित फल मिलता है। अत: भैरव जी की पूजा-अर्चना करने व कालाष्टमी के दिन व्रत एवं षोड्षोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कालभैरव का दर्शन एवं पूजन मनवांछित फल प्रदान करता है।

व्रत की विधि भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों को भैरवनाथ की षोड्षोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देनी चाहिए। रात्रि के समय जागरण कर शिव एवं पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए। भैरव कथा का श्रवण और मनन करना चाहिए। मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाडा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान भैरवनाथ का वाहन 'श्वान' (कुत्ता) है। अत: इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन प्रात:काल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत, पिशाच एवं काल भी दूर रहते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी कार्य करते हैं, उनमें इन्हें सफलता मिलती है।

माहात्म्य कालाष्टमी के दिन काल भैरव के साथ इस दिन देवी कालिका की पूजा-अर्चना एवं व्रत का भी विधान है। काली देवी की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद मां की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार दुर्गापूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। भैरव की पूजा-अर्चना करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि के साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रहम कवच आदि का नियमित पाठ करने से अनेक समस्याओं का निदान होता है।

कथा भैरवाष्टमी या कालाष्टमी की कथा के अनुसार एक समय श्रीहरि विष्णु और ब्रहमा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इस हद तक बढ गया कि समाधान के लिए भगवान शिव एक सभा का आयोजन करते हैं। इसमें ज्ञानी, ऋषि-मुनि, सिद्ध संत आदि उपस्थित थे। सभा में लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रहमा जी संतुष्ट नहीं होते। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांतचित शिव यह अपमान सहन न कर सके और ब्रहमा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोक भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रूद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। वह श्वान पर सवार थे, उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे 'दंडाधिपति' कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। उनके रूप को देखकर ब्रहमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान भोलेनाथ एवं भैरव की वंदना करने लगे। ब्रहमा, देवताओं और साधुओं द्वारा वंदना करने पर भैरव जी शांत हो जाते हैं।

क्यूं की जाती है गणेश-लक्ष्मी की पूजा एक साथ

दीपावली के दिन हम धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह हम सब भली भांती जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बगैर कभी पूरा नहीं होता।

गणेश जी बुद्धि प्रदान करते हैं। वे विघ्न विनाशक और विघ्नेश्वर हैं। यदि व्यक्ति के पास खूब धन-सम्पदा है और बुद्धि का अभाव है तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पायेगा। इसलिए व्यक्ति का बुद्धिमान और विवेकी होना भी आवश्यक है। तभी धन के महत्व को समझा जा सकता है। गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा के महत्त्व को कई कहानियों के माध्यम से बताया गया है। आइये जाने ऐसी ही कहानी।

शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी को धन और संब्रद्धि का प्रतीक माना गया है। जिसकी वजह से लक्ष्मी जी को इसका अभिमान हो जाता है। विष्णु जी इस अभिमान को खत्म करना चाहते थे इसलिए उन्हों ने लक्ष्मी जी से कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक वह माँ ना बन जाये। लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए यह सुन के वे बहुत निराश हो गयी। तब वे देवी पार्वती के पास गयी मदद मांगने के लिए।

जानिए दीवाली पर क्यों किया जाता है लक्ष्मी पूजन

पार्वती जी को दो पुत्र थे इसलिए लक्ष्मी जी ने उनसे एक पुत्र को गोद लेने को कहा। पार्वती जी जानती थी कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर लंबे समय नहीं रहती हैं। इसलिए वे बच्चे की देख भाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उन्हें सौप दिया।

इससे लक्ष्मी जो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि वे गणेश का बहुत ध्यान रखेंगी। और जो सुख और संब्रद्धि के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उन्हें उनसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पडेगी, तभी मेरी पूजा संपन्न होगी। तब से आज तक दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चंपत राय से पूछताछ मथुरा पर भी आंच

लखनऊ। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच जांच चल रही है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुधवार को ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से पूछताछ की है.सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ का केंद्र दान में मिले पैसों, मंदिर के भीतर की व्यवस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका रही है. एसआईटी ने केवल शीर्ष अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि दान की रकम गिनने और ट्रस्ट के रिकॉर्ड संभालने वाले कर्मचारियों से भी विस्तार से जानकारी जुटाई है. बताया गया कि एसआईटी में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, इंस्पेक्टर जनरल किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन ने चंपत राय और गोपाल राव से अलग-अलग पूछताछ की है. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को पूछताछ प्रक्रिया से दूर रखा गया. जांच टीम ने सवालों के जरिए यह समझने की कोशिश की कि दान की रकम के संग्रहण, रिकॉर्डिंग और प्रबंधन की प्रक्रिया किस तरह संचालित होती है।

संपर्क में हैं सपा सांसदः केशव

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के दावों से सियासी तापमान बढ़ गया है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने और पाला बदलने की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सपा को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही, लेकिन वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी में स्वाभाविक रूप से बड़ी टूट देखने को मिल सकती है. केशव मौर्य ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई टूट का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में कई नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं.इससे पहले प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी. राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जल्द बड़ी टूट हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है।

कर्नाटक में बिदादी टाउनशिप पर बवाल

नागार्जुन। कर्नाटक के बिदादी में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है. राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में अब स्थानीय किसानों ने सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किए हैं. सैकड़ों किसानों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत दखल देने और जबरन जमीन छीनने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है. इस आंदोलन को लेकर जनता दल के नेता निखिल कुमार ने सोशल मीडिया पर किसानों के दर्द को बयां किया है. अब उनकी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों स्थानीय किसानों ने सीधे राहुल गांधी को अपनी व्यथा और गुस्सा लिखकर भेजा है. अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों में 80त से ज्यादा छोटे किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं. किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार 33,000 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट एजेंडे को पूरा करने के लिए उपजाऊ जमीन छीन रही है।

मुझे मार दो या खान के खिलाफ एफआईआर करो

पटना। पटना के कदमकुआं थाना में ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद ने फैजल खान (खान सर) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है. रौशन आनंद का आरोप है कि आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. इसे लेकर उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 घंटे हो गए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई. रौशन आनंद ने कहा कि मुझे मार दो या खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो. जब तक एफआईआर नहीं होगी मैं यहीं रहूंगा. रौशन आनंद ने कहा कि जब तक उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक वह थाना परिसर के बाहर धरना जारी रखेंगे. इस दौरान उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र भी कदमकुआं थाना पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।

विधानसभा चुनाव 2027: पंजाब कांग्रेस में बदलाव की आहट

नईदिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी नेतृत्व को चिंता है कि गुटबाजी, कई पावर सेंटर और अंदरूनी खींचतान का फायदा विरोधी दल उठा सकते हैं. यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब पर फोकस बढ़ा दिया है.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के साथ पंजाब के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की है. इस बैठक का मकसद संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियों और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं का आकलन करना है. इसके बाद पार्टी ने अजय माकन समेत तीन सदस्यों की एक ऑब्जर्वर कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी को पंजाब की स्थिति का मूल्यांकन करने और भविष्य की रणनीति पर सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है. कमेटी की रिपोर्ट से पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम तय होगा. पंजाब को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की गंभीरता लगातार बढ़ती बैठकों से साफ दिखाई दे रही है. पिछले दो सप्ताह में ही पार्टी ने पंजाब मामलों पर चार महत्वपूर्ण बैठकें की हैं. इससे ये संकेत मिलता है कि हाईकमान चुनाव से काफी पहले संगठनात्मक कमियों को दूर करना चाहता है।

शिवसेना यूबीटी में बगावत पर एक्शन! 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस

नईदिल्ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने गुरुवार को उन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो संसदीय दल की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी सांसद अनिल देसाई ने कहा कि बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है और अनुपस्थित रहने वाले सभी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे गैर-हाजिरी का कारण पूछा गया है।

देसाई ने कहा कि बैठक अभी खत्म हुई है, आज ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जब उनसे पूछा गया कि बैठक में शामिल न होने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई यही है- कारण बताओ नोटिस। उनसे पूछा जाएगा कि वे क्यों नहीं आए। जो लोग नहीं आए, उन सभी को नोटिस दिया जाएगा। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पार्टी सभी गैर-मौजूद सांसदों से जवाब मांगेगी, देसाई ने कहा, हां, सभी को नोटिस भेजा जाएगा। गैर-मौजूद सांसदों से खास तौर पर क्या पूछा जाएगा, इस पर शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि सवाल कुछ ऐसे होंगे- आपको जानकारी दी गई थी, आपको मैसेज भेजा गया था, आपको वाट्सअप किया गया था, और आपको वह मिला भी था। फिर भी आपने यह नहीं बताया कि आप आ रहे हैं या नहीं, इसलिए आपकी गैर-मौजूदगी को इसी नज़रिए से देखा जाएगा।

इस बीच, बैठक में शामिल होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे ने बताया कि बैठक में छह सांसद मौजूद नहीं थे। उनमें ओमराजे निम्बालकर (धरशिव), संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व), संजय जाधव (परभणी), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल अष्टिकर (हिंगोली), भाऊसाहेब वकचौरे (शिरडी) हैं।

बाकी छह बागी सांसदों ने इससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी। पार्टी के भीतर किसी भी संभावित बगावत को शुरू में ही रोकने के लिए उद्धव ठाकरे के निर्देश पर दिल्ली के पुराने संसद भवन में एक ज़रूरी बैठक बुलाई गई। सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर (हाज़िरी रजिस्टर) तैयार किया गया था। हालाँकि, बैठक में केवल नीचे दिए गए प्रमुख नेता और सांसद ही शामिल हो पाए।

ठाकरे गुट में चिंता काफी बढ़ गई है क्योंकि संजय राउत (राज्यसभा सांसद), अनिल देसाई (चीफ व्हिप), अरविंद सावंत (लोकसभा ग्रुप लीडर) और राजाभाऊ वाजे (नासिक सांसद) के अलावा छह और सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद, संजय राउत और अरविंद सावंत भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद के लिए रवाना हो गए हैं।

बागी सांसदों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। क्या अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है? ठाकरे गुट के नौ लोकसभा सांसदों में से छह बागी सांसदों के एक समूह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क किया है और एक अलग समूह के तौर पर मान्यता मांगी है। इन बागी नेताओं को कानूनी तौर पर घेरने के लिए, ठाकरे गुट ने सभी नौ सांसदों को थ्री-लाइन व्हिप जारी किया था।

जिसमें उनका व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य था। अब, जब छह सांसद इस व्हिप का उल्लंघन करते हुए अनुपस्थित रहे, तो ठाकरे गुट उन्हें अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, बागी सांसद अभी तक सामने नहीं आए हैं और इंतजार करो और देखो का रुख अपनाए हुए हैं।

खबर है कि पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से कम से कम छह एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं। इससे पार्टी में एक और फूट की आशंका बढ़ गई है, ठीक वैसी ही जैसी 2022 में शिंदे की अगुवाई में हुई थी, जिससे पार्टी दो गुटों में बंट गई थी।

छह बागी सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे अटकलें और तेज हो गईं। तुरंत ही उद्धव ठाकरे को गायब सांसदों के बारे में जानकारी दी गई। अब गैर-हाजिर सांसदों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा चल रही है।

उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी सांसदों के पाला बदलने पर जताई चिंता

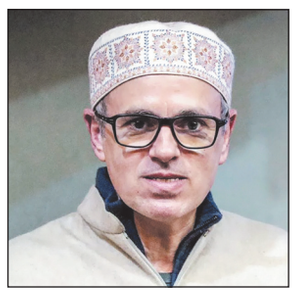

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के सांसद केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो और राज्यसभा में तीन सदस्य हैं। तृणमूल कांग्रेस के 22 और शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों द्वारा केंद्र सरकार का समर्थन किए जाने की खबरों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला ने बांदीपुरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''इस सवाल का जवाब न तो मैं दे सकता हूं और न ही आप।

अब्दुल्ला ने बांदीपुरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, %%मैं कैसे कह सकता हूं कि द्रमुक या शिवसेना के सांसद क्या करेंगे? यह उन पर निर्भर करता है। यह उनकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है। उनकी अंतरात्मा उन्हें जहां तक ले जाएगी, वे वहां तक जाएंगे।'' अब्दुल्ला ने कहा, ''जहां तक नेकां के सांसदों का सवाल है, हम भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार का कभी समर्थन नहीं करेंगे।''

हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना की। बाद में मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा, 22 जून को खीर भवानी मेले का शुभ अवसर है। दुनिया भर से लोग देवी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां इकट्ठा होंगे। यहां का विधायक होने के नाते, मैं यह देखने आया हूं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या काम बाकी है। यहां के पुजारियों से बात करने के बाद मुझे पता चला है कि 2-3 चीजों की ज़रूरत है। हम 22 जून से पहले इन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दावा

मोदी सरकार के 12 साल विकास विरासत का स्वर्णिम संगम!

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल विकास और विरासत के संगम के रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम युग रहे हैं। इन 12 वर्षों में, एक ओर जहां श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर पीएम आवास, आयुष्मान भारत, अन्न भंडार, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं और पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार विकास भी, विरासत भी की थीम के तहत पिछले 12 वर्षों में की गई विभिन्न पहलों को उजागर कर रही है। सरकारी बयान के अनुसार, विरासत संरक्षण को व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विकास और प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बयान में कहा गया है कि मुख्य पहलों में एक करोड़ रिकॉर्ड का डिजिटाइज़ेशन, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के 11 म्यूज़ियम बनाना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शामिल है।

इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में मशहूर जगहों को फिर से ठीक करने, मंदिरों और स्मारकों को संरक्षित करने, आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और हेरिटेज शहरों व तीर्थयात्रा सर्किट को विकसित करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत की सांस्कृतिक संपत्तियां - जिनमें स्मारक, प्राचीन वस्तुएं, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं - पीढ़ियों से चली आ रही एक साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें आगे कहा गया है कि 2014 से सरकार ने इन संपत्तियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, साथ ही विरासत के विकास को आर्थिक विकास, पर्यटन, आजीविका और सांस्कृतिक कूटनीति से जोड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विरासत के संरक्षण को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की कोशिश की है। इसमें चोरी हुई 668 से ज़्यादा प्राचीन वस्तुओं की वापसी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर जैसे आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और भारतीय परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों पर ज़ोर दिया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा नया इतिहास

न्यूयॉर्क। टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। मैच के दौरान, पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान पर उतरते ही एक रिकॉर्ड बना दिया। वह टूर्नामेंट के इतिहास में मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज़ आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। 41 साल और 132 दिन की उम्र में, रोनाल्डो ने कनाडा के अतिबा हचिंसन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के खिलाफ 39 साल और 296 दिन की उम्र में मैच शुरू किया था।

रोनाल्डो टूर्नामेंट के इतिहास में छह फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। अब वह इस रिकॉर्ड के मामले में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मैच के दौरान रोनाल्डो ने 25 बार बॉल को छुआ (टच किया) और तीन शॉट भी लगाए। उनके करियर में वर्ल्ड कप के किसी मैच की शुरुआत में यह दूसरा सबसे कम टच का आंकड़ा था। इससे बड़े टूर्नामेंट में उनके फ़ॉर्म को लेकर चिंता और निराशा बढ़ गई है। रोनाल्डो अब किसी बड़े टूर्नामेंट में लगातार 10 मैचों से कोई गोल नहीं कर पाए हैं। मैच में जोआओ नेवेस ने छठे मिनट में शानदार हेडर से पहला गोल करके अपनी छाप छोड़ी। बाद में, डीआर कांगो के योआने विसा ने भी बेहतरीन हेडर से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में पुर्तगाली खिलाड़ियों को लगा कि उन्होंने फिर से बढ़त बना ली है, जब जोआओ कैंसेलो ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण उस गोल को अमान्य करार दिया गया। बाद में, सब्स्टीट्यूट फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ने रोनाल्डो के लिए मौके बनाए, लेकिन 41 वर्षीय स्ट्राइकर उन मौकों को गोल में बदलने में नाकाम रहे। आखिरी समय में दबाव बनाने के बावजूद पुर्तगाल जीत हासिल नहीं कर सका।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 254 अंक चढ़ा निफ्टी 24150 के पार

नई दिल्ली। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की सख्त टिप्पणियों के कारण गुरुवार की सुबह लाल निशान में खुले भारतीय शेयर बाजार ने दिन के अंत तक शानदार वापसी की है। मजबूत खरीदारी के दम पर शेयर बाजार ने शुरुआती दबाव को पछाड़ते हुए लगातार पांचवें दिन बढ़त का सिलसिला कायम रखा है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक मजबूत रिकवरी दर्ज की। दिन के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 254.36 अंक (0.32 प्रतिशत) की शानदार बढ़त के साथ 77,409.98 के ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.30 अंक (0.34 प्रतिशत) उछलकर 24,168.00 के पार निकल गया, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। कारोबारी सत्र की शुरुआत में बाजार लाल निशान में खुला था।

20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से बचेगा 1 करोड़ टन कच्चा तेल!

नईदिल्ली। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक जहां पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी सीमित थी, वहीं अब देश 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य तक पहुंच चुका है। अब संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वर्षों में इसे 30% तक ले जाने की तैयारी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा देश को विदेशी मुद्रा बचत के रूप में मिल रहा है। साथ ही किसानों, डिस्टिलरी कंपनियों और एथेनॉल उद्योग को भी इससे फायदा हो रहा है। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सालाना करीब 1,200 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ सकती है। देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता अब 2,000 करोड़ लीटर के आसपास पहुंच चुकी है और सप्लाई की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है।

कच्चा तेल सस्ता : भारत में क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?

त्रिशूर। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की दर कम होने पर ईंधन की कीमतों में तुरंत कमी नहीं की जा सकती है। क्योंकि इसमें कई कारण शामिल हैं, जिनमें सस्ता तेल भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि के बारे में कहा कि इससे केवल लगभग 3.94 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का ही प्रभाव पड़ा है। लेकिन कच्चे तेल की लागत वैश्विक स्तर पर कम होने के कारण इसे तुरंत वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, %इसमें समय लगेगा क्योंकि सस्ते कच्चे तेल को होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत तक पहुंचाना होगा, जिससे जहाजों की आवाजाही में अधिक वृद्धि होगी। इसलिए स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा।

देश में गोल्ड इम्पोर्ट 70 प्रतिशत घटा

नईदिल्ली। देश में गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के सरकार के प्रयासों के बड़े परिणाम सामने आने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोने पर सीमा शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बाद देश में सोने के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बृहस्पतिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले के बाद देश में सोने का आयात करीब 70 प्रतिशत घटकर महज 25-30 टन रह गया है। मूल्य के लिहाज से हालांकि, मई में सोने का आयात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 3.41 अरब डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण ऊंची कीमतें रहीं। अप्रैल-मई के दौरान सोने का आयात 60.14 प्रतिशत बढ़कर 9.04 अरब डॉलर हो गया।

औद्योगिक सब्सिडी के बेहतर विकल्प से चीन का मुकाबला

अभिजीत मुखोपाध्याय

ओइसीडी यानी ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जून, 2026 की मैजिक डाटाबेस रिपोर्ट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह बताती है कि औद्योगिक सब्सिडी अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा की एक संरचनात्मक विशेषता बन चुकी है। चीन इसका बड़ा उदाहरण है। रिपोर्ट बताती है कि सब्सिडियां किसी देश के नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं, पर वे व्यापार और प्रतिस्पर्धा को उलट-पलट भी सकती हैं। यहां भारत के लिए व्यावहारिक प्रश्न यह है कि रक्षात्मक या प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाये बगैर कंपनियों की रक्षा कैसे की जाये, उनकी नीतिगत स्वतंत्रता कैसे बनाये रखी जाये और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को किस तरह से मजबूत किया जाये।

इसका उचित उत्तर व्यापारिक सुरक्षा उपायों, घरेलू क्षमता निर्माण, अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण औद्योगिक नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का मिश्रण होगा। भारत के लिए इस रिपोर्ट का मुख्य निहितार्थ यह है कि चीनी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा हमेशा समान रूप से समर्थित कंपनियों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि विदेशी प्रतिस्पर्धियों को अधिक अनुदान, कर रियायतें या बाजार दर से कम लागत पर वित्तीय सहायता मिलती है, तो भारतीय कंपनियों को ऐसी लागत संरचना का सामना करना पड़ सकता है, जिसका मुकाबला केवल निजी प्रयासों से करना कठिन होगा। इसका नतीजा आयातित वस्तुओं की कीमतों के दबाव, घरेलू उत्पादकों के घटते लाभांश और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश के कम प्रोत्साहन के रूप में सामने आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत को हर विदेशी सब्सिडी की नकल करनी चाहिए।

इसका अर्थ यह है कि हमारी घरेलू नीतियां अपने उत्पादकों को विश्व बाजार में अनुचित असमानताओं के प्रति असुरक्षित न छोड़ें। इसलिए भविष्य-दृष्टि वाली औद्योगिक रणनीति का ध्यान केवल सब्सिडी की मात्रा को रुपये के आधार पर बराबर करने के बजाय लचीलापन, पैमाना और उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए।

भारत के पास पहले से ही व्यवसायों को समर्थन देने वाली कई नीतियां हैं, पहला कदम व्यापारिक सुरक्षा उपाय होना चाहिए- एंटी डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, संरक्षणात्मक कार्रवाई तथा उन क्षेत्रों में आयात वृद्धि की करीबी निगरानी, जहां सब्सिडी से उत्पन्न बदलाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरा क्षेत्र घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता का है। अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, बिजली की विश्वसनीयता, कौशल विकास, परीक्षण सुविधाओं, मानकों और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए सरकार मदद बढ़ा सकती है। ये सभी उपाय अक्षमता को प्रोत्साहित किये बिना उत्पादन लागत कम करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में स्थिर इनपुट पारिस्थितिकी तंत्र अक्सर बड़ी सब्सिडी से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसी नीतिगत रूपरेखा, जो संचालन संबंधी बाधाओं को कम करे, वह नकद अनुदान जितनी ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकती है। तीसरा कदम अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय सहायता है। यदि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाये, तो उन्हें निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन, ऊर्जा दक्षता, स्थानीय मूल्य संवर्धन और अनुभव आधारित सीखने जैसे परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। भारत की व्यावहारिक रणनीति पांच स्तंभों पर आधारित हो सकती है। पहला, एक सक्रिय सब्सिडी निगरानी प्रकोष्ठ का गठन हो, जो आयात प्रधान क्षेत्रों पर नजर रखे, संभावित विकृतियों की पहचान करे और व्यापारिक सुरक्षा उपायों के लिए प्रमाणिक दस्तावेज तैयार करे। जिन वस्तुओं का हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, यदि उन्हें उनके मूल देश में सरकारी सब्सिडी मिल रही है, तो हमें तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे, भारत को 'रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी' उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां स्केल इकोनॉमी (बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाले संभावित लाभों वाली अर्थव्यवस्था) और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बड़ी महत्वपूर्ण है।

सीटों की संख्या को बढ़ाने का सुखद परिणाम

ट्राइबल हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने रचा कीर्तिमान

- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा सीटें 50 से बढ़ाकर 200 किए जाने का मिला सकारात्मक परिणाम
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई, कहा- युवा शक्ति की सफलता विकसित छत्तीसगढ़ की नई पहचान
- दूरस्थ जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराई दमदार मौजूदगी

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के परिणामों में छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे 13 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। विशेष बात यह है कि इनमें अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर निर्माण के लिए बेहतर अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन युवाओं की सफलता प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की प्रेरणा देगी।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में सफल होने वाले विद्यार्थियों में गौतम कुमार, कुलभूषण सिंह पोया, हरि चंद्र प्रकाश सिंह, मयंक रात्रे, मलिकराम पटेल, आर्यन राठौर, चेतन लाल, हरीश कुमार पटेल, किशन लाल साहू, सत्यनारायण चंद्राकर, सु दीक्षा दिवाकर, विकेश कुर्रे तथा प्रकाश पटेल शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज के वंचित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों, जनजातीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर प्राप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यहां चयनित विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग तथा अनुभवी विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष पद पर संजय अग्रवाल की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल 2017 तथा योग आयोग नियम-2017 के प्रावधानों के तहत की गई है। अध्यक्ष का कार्यकाल योग आयोग नियम, 2017 की कंडिका-6 (3) के अनुसार अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, के लिए होगा।यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार योग को स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, संतुलन और सकारात्मकता का भी संचार करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता एवं योग आधारित स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

उच्च शिक्षा में बड़े सुधार की तैयारी: नए सत्र में समय पर होंगी परीक्षाएं

रायपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नवीन शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर राज्य के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सत्र में शैक्षणिक कैलेंडर का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और अनुशासित बनेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, अनुशासित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के क्रियान्वयन, डिजिटल गवर्नेंस के उपयोग, एकीकृत नियामक संस्थाओं के गठन और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश शामिल हैंद्य उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसरों में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए बनेगा हेल्प डेस्क

छात्र हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री श्री वर्मा ने घोषणा की है कि महाविद्यालय आने वाले समस्त विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए %हेल्प डेस्क% की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें तत्काल राहत मिलेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालयों में गुणाक्रम (मेरिट) के आधार पर समय पर प्रवेश लें। उन्होंने कहा कि समय पर प्रवेश होने से प्राविण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में आने वाले सभी विद्यार्थियों का एडमिशन निर्धारित समय में पूरा हो सकेगा और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। बार-बार प्रवेश की तिथि बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि प्रवेश सूची में नाम आने पर कोई भी विद्यार्थी दाखिले से वंचित न रहे।

सभी कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत पढ़ाई समय पर शुरू हो, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, और सेमेस्टर व अन्य परीक्षाएं समय पर आयोजित की जाएं।

नीट यूजी 2026 अभ्यर्थियों के लिए सिम्स में 24×7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन

रायपुर। नीट यूजी 2026 परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर ने अभ्यर्थियों के लिए 24म7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार सिम्स के मनोरोग विभाग के माध्यम से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यार्थियों को समय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श और भावनात्मक सहयोग मिल सके।

सिम्स अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोबाइल नंबर 9425502353 को 18 जून 2026 से आगामी दो सप्ताह तक हेल्पलाइन नंबर के रूप में संचालित किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम, काउंसिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया एवं भविष्य को लेकर होने वाली चिंता, तनाव, घबराहट अथवा अन्य मानसिक समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका शैक्षणिक प्रदर्शन। नीट जैसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के दौरान अनेक विद्यार्थी मानसिक दबाव का सामना करते हैं। ऐसे समय में उचित परामर्श एवं सकारात्मक संवाद उन्हें तनाव से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुजीत नायक ने बताया कि परीक्षा परिणाम अथवा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तनाव, चिंता, निराशा और असफलता का भय जैसी स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन समय पर परामर्श मिलने से इन समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।

महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्ति एक अमर मिसाल है : अरुण साव

रायपुर। भारत की पुण्य भूमि ने अनेक वीर योद्धाओं और महापुरुषों को जन्म दिया है। वीर योद्धा महाराणा प्रताप ऐसे ही महान सपूत थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान और राष्ट्र धर्म से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने मुगल सत्ता की दासता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया। उनका जीवन आज भी समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी में सर्वोदय राजपूत राठौर क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित वीर महाराणा प्रताप जयंती समारोह में महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और साहस को नमन करते हुए ये बातें कही। उन्होंने समारोह में महाराणा प्रताप की अष्टधातु प्रतिमा के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मंत्र 'राष्ट्र प्रथम' हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। भारत त्याग और बलिदान की भूमि है। इसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए समाज को संगठित रहना होगा। राजपूत समाज शिक्षा, खेल, सरकारी सेवाओं और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजपूत समाज के शिक्षकों, डॉक्टरों, खेल प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, पूर्व सैनिकों, समाजसेवियों, गौसेवकों तथा कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में 55 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अभनपुर में होगा कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर अभनपुर स्थित अग्रवाल रिसोर्ट में आयोजित है। यह शिविर 20 से 29 जून के मध्य पूरी तरह ये आवासीय शिविर होगा। इस शिविर में एआईसीसी का प्रशिक्षण विभाग प्रशिक्षण देगा। जिला अध्यक्षों

को फील्ड विजिट एवं अन्य सकारात्मक सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी भी 21 जून को एक दिन के लिए शामिल होंगे। शिविर एआईसीसी के सभी राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल होंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट एवं प्रभारी सचिव भी शिविर में शामिल होंगे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे तथा 2.45 बजे प्रशिक्षण स्थल आयेंगे तथा 5.30 बजे तक प्रशिक्षण स्थल में रहेंगे तथा शाम को 6.45 बजे नियमित विमान से दिल्ली रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी के संदर्भ में केदार कश्यप का बयान बेहद ही आपत्ति जनक और निंदनीय है।

भाजपा राज में रेत माफिया बेलगाम हो गया है : शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के लोग रेत के लिये खूनी खेल, खेल रहे हे। कोरिया में एक भाजपा नेता के द्वारा दूसरे भाजपा नेता को उसके भाई के साथ जिंदा जला देना बताता है कि भाजपाई पैसे के लिये कुछ भी कर सकते है। उनमें कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। यह

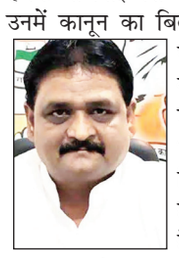

घटना राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था का भी उदाहरण है। हत्या करने वाला भाजपा नेता को स्थानीय विधायक का भी खुला संरक्षण हासिल है, ऐसा बताया जा रहा है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रेत का यह खूनी खेल बताता है कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। अराजक तत्व और अपराधियों को सत्ताधीशों का संरक्षण है तथा पुलिस अपराधियों के सामने बौनी बनी हुई है। अपराधी गोली, चला रहे, जिंदा जला रहें, चाकू मार रहे है। भाजपा सरकार की पुलिस बेचारी बनी हुई है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बमुश्किल एक महीने पहले जांजगीर-चांपा के जैजेपुर में घर में घुसकर के दो भाईयों को गोली मार दी जाती है। कुछ दिनों पहले बलरामपुर में रेत माफिया ने पुलिस कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ा कर हत्या कर दिया।

भाजपा ने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया: वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, प्रंदेश अवैध शराब का गढ़ बन चुका है। प्रदेश के गांव-गांव, गली, कूचे में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। सरकारी अमला इस अवैध शराब बिक्री को खुला संरक्षण देता है। आबकारी मंत्री दावा करते है शराब के पैसे

से सरकार चल रही है। मंत्री दयालदास बघेल स्वयं बता रहे कि किसी आदमी के 1 बोतल शराब मिल जाये तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर देती है, शराब भट्ठी से पेटी-पेटी शराब लेकर खुलेआम बेची जा रही कार्यवाही नहीं होती है। मंत्री बघेल ने स्वीकार किया कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग दोनों जिम्मेदार है।प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य की जनता को शराबी बनाने पर तुली है। विपक्ष में रहकर शराबबंदी के लिए कसमें खाने वाली, शराबबंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या दुगुनी कर दिया है। राज्य में लगभग 700 देशी और अंग्रेजी शराब दुकाने थी। भाजपा सरकार ने हर देशी शराब दुकानों में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी शराब दुकानों में देशी बेचना शुरू कर दिया है।

योजनाओं से बदल रही देश और गांवों की तस्वीर: देवांगन

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रवास के दौरान मंगली बाजार, गौरेला स्थित सांस्कृतिक भवन में आयोजित प्रबुद्धजन एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मुख्य

अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया।अपने संबोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार का गठन जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सफलता का प्रमाण है। यह 140 करोड़ भारतीयों की विकास यात्रा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक है। भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

जीएसटी कानून की सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा:पारवानी

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, महामंत्री अवनीत सिंह, कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय, पगारिया कॉम्प्लेक्स, पंडरी में एक महत्वपूर्ण जीएसटी जागरूकता एवं अनुपालन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में व्यापारियों, उद्यमियों, करदाताओं, ट्रांसपोर्टर्स एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर जीएसटी कानून, विभागीय जांच, नोटिस, समन, ऑडिट, फर्जी आईटीसी तथा व्यापारियों के कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्वागत उद्बोधन प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन ने दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता एवं प्रसिद्ध जीएसटी विशेषज्ञ सीए जितेन्द्र सिंह खनूजा का स्वागत प्रदेश चेयरमैन जितेन्द्र दोशी एवं विक्रम सिंहदेव द्वारा किया गया।

ऐतिहासिक उपलब्धि: छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारत महाअभियान पूरा

तीन महीनों में मिलीं 11 हजार 808 दुर्लभ पांडुलिपियां

- दुर्लभ पांडुलिपियां सहेजने की दिशा में महासमुंद जिला अव्वल

रायपुर। दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने की दिशा में डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण सबसे प्रभावी कदम हैं। भारत सरकार और राज्य के संस्कृति विभाग %ज्ञान भारतम% (ज्ञान भारत) जैसे अभियानों के तहत ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे सैकड़ों वर्ष पुराने ग्रंथों को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम् मिशन के तहत राज्य में चले तीन महीने के सघन सर्वेक्षण में कुल 11 हजार 808 दुर्लभ पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। 15 मार्च से 15 जून 2026 तक चले इस अभियान के जरिए सदियों पुराना प्राचीन ज्ञान अब डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित हो सकेगा।

इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के समन्वय से ज्ञान भारतम् मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया गया। इस दौरान निजी संग्रहों, प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और पारिवारिक धरोहरों में छिपी

ताड़पत्र व कागज की अमूल्य पांडुलिपियां सामने आईं, जिनमें ताड़पत्रों की संख्या सर्वाधिक है।

सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में साहित्य और ज्ञान की समृद्ध परंपरा बिखरी हुई थी। इसमें महासमुंद जिले से 3,498 पांडुलिपियों की संख्या सर्वाधिक के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। रायपुर जिले में 1,770 पांडुलिपियां मिली, जिससे दूसरे स्थान पर रहा। बस्तर जिले में 1,610 पांडुलिपियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। रायगढ़ जिले में 1,553 पांडुलिपियां पंजीबद्ध की गईं। इसके अलावा कोरबा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली और कोरिया जिलों से भी भारी मात्रा में दुर्लभ दस्तावेज मिले हैं।

ज्ञान भारतम् मिशन के राज्य नोडल अधिकारी श्री प्रभात सिंह ने बताया कि इन पांडुलिपियों में धर्म, आध्यात्म, कर्मकांड, वैदिक चिकित्सा (आयुर्वेद), ज्योतिष, दर्शन, इतिहास तथा स्थापत्य कला से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि ताड़पत्रों पर मुख्य रूप से उड़िया भाषा और उड़िया लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि कागज पर लिखित पांडुलिपियों में देवनागरी लिपि के साथ ब्रज भाषा और अवधी भाषा देखने को मिलती है। यह विविधता छत्तीसगढ़ के प्राचीन सांस्कृतिक संपर्कों और ऐतिहासिक आदान-प्रदान को प्रमाणित करती है।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा केवल इन पांडुलिपियों का पंजीयन और दस्तावेजीकरण किया गया है।

सऊदी अरब से नागपुर आया छत्तीसगढ़ के 122 हाजियों का पहला जत्था

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के माध्यम से हजयात्रा पर गए हजयात्रियों की सऊदी अरब से वतन वापसी प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने बताया है कि आज 18 जून 2026 को राज्य के 122 हाजियों की नागपुर सकुशल वापसी हुई है। हाजियों का पहला जत्था आज नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। श्री बेग ने बताया कि नागपुर एयरपोर्ट पर समस्त हाजियों को 5-5 लीटर मक्का का पवित्र जल श् आबे ज़म-ज़मश् प्रदान किया गया ।

नागपुर एयरपोर्ट पर हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज़ बेग सहित हज कमेटी के अन्य लोगों ने हाजियों का इस्तेकबाल किया और उनकी गुलपोशी की । सऊदी अरब से स्वदेश वापसी पर समस्त हाजियों के चेहरों पर सुकून और खुशी नज़र आई। हाजियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी , देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्था हेतु आभार व्यक्त किया है।

इस अवसर पर राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग, सदस्य मौलाना अमीर बेग, मौलाना हसन अब्बास, हज कमेटी ऑफिस सहायक सैय्यद सलीम उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.